RNI No. DELMUL/2012/47011

08 अगस्त, 2026 शनिवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 128

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

इंग्लैंड के 25 वर्षीय गेंदबाज जॉन टर्नर ने क्रिकेट को कहा अलविदा 07

संक्षिप्त वार्ता

राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ीं: बैंक ने संपत्तियां कीं कुर्क

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की परेशानियां रुक नहीं रही हैं। चेक बाउंस मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे अभिनेता के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज वसूली की प्रक्रिया तेज की है। बैंक ने राजपाल पर बकाया 16 करोड़ 61 लाख रुपये से अधिक के ऋण की वसूली के लिए शाहजहांपुर स्थित उनकी दो संपत्तियों को नीलामी के लिए चिह्नित कर नोटिस चस्पा किया है।

यह कर्ज राजपाल ने अपनी फिल्म अता पता लापता के निर्माण के लिए लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिसके चलते वे ऋण की किस्तों का समय पर भुगतान नहीं कर सके और धीरे-धीरे ब्याज बढ़ता गया, जिससे यह रकम अब 16 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई शाखा ने शाहजहांपुर शहर में स्थित एक संपत्ति और गांव में स्थित खेत व मकान को अपने कब्जे में लेकर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। इन दोनों संपत्तियों का आरक्षित मूल्य 3 करोड़ 19 लाख 26 हजार रुपये तय किया गया है और इनकी ई-नीलामी 9 सितंबर 2026 को निर्धारित है।

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश, येलो अलर्ट जारी

नई दिल्ली। दिल्ली सहित पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम ने फिर करवट बदली है। बीती देर रात से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित विभिन्न इलाकों में लगातार हो रही झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार, 7 अगस्त के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें सुबह और पूर्वाह्न के दौरान मध्यम से भारी वर्षा की चेतावनी है। इस झमाझम बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत दी है, वहीं कई प्रमुख मार्गों पर जलभराव और टूटी सड़कों पर बने गहरे गड्ढों ने यातायात को बुरी तरह बाधित किया है। लगातार दो दिनों की बारिश से अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि, सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों और स्कूल वाहनों को सड़कों पर लंबी कतारों के कारण खासी परेशानी झेलनी पड़ी।

सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया बोफोर्स मामले का कानूनी अध्याय

न्यायालय ने बंद की फाइल, हिल गई थी राजीव सरकार

वेब वार्ता, नई दिल्ली। करीब चार दशक से देश की राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे बोफोर्स घोटाले का कानूनी अध्याय अब पूरी तरह बंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के वर्ष 2005 के फैसले को चुनौती देने वाली अंतिम लंबित याचिका खारिज कर दी। इसी के साथ हिंदूजा बंधुओं और स्वीडिश हथियार निमार्ता कंपनी एबी बोफोर्स को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बची आखिरी न्यायिक चुनौती भी समाप्त हो गई।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दो दिवंगत प्रतिवादियों के नाम हटाने के लिए समय मांगे जाने पर इसे स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि जब संबंधित कार्यवाही पहले ही समाप्त हो चुकी है और मामला वर्षों पुराना है, तब इसे आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद

अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

इस फैसले के साथ बोफोर्स मामले में सभी कानूनी चुनौतियों का अंत हो गया। इससे पहले वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील भी खारिज कर दी थी। अदालत ने माना था कि अपील निर्धारित समय से 4,522 दिन की देरी से दायर की गई थी और देरी का संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 मई 2005 को हिंदूजा बंधुओं और एबी बोफोर्स के खिलाफ सभी आपराधिक आरोप रद्द कर दिए थे। उस समय अदालत ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस मामले की जांच में सरकारी संसाधनों का व्यापक उपयोग हुआ, लेकिन अभियोजन अपने आरोपों को प्रभावी ढंग से साबित नहीं कर सका।

बोफोर्स मामला वर्ष 1986 में भारतीय सेना के लिए 155 मिमी हॉवित्जर तोपों की खरीद से जुड़े 1,437 करोड़ रुपये के रक्षा सौदे से जुड़ा था। वर्ष 1987 में इस सौदे में कथित तौर पर अवैध कमीशन दिए जाने के आरोप सामने आए, जिसके बाद यह देश के सबसे चर्चित राजनीतिक विवादों में शामिल हो गया। इसके बाद सीबीआई ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर और आरोपपत्र दाखिल किए, लेकिन समय के साथ कई आरोपी दिवंगत हो गए और विभिन्न अदालतों के फैसलों के बाद मामला धीरे-धीरे कमजोर पड़ता गया। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के साथ इस बहुचर्चित मामले का कानूनी पटाक्षेप हो गया है।

किस मंत्री को जवाब देना है, यह विपक्ष तय नहीं करेगा

राज्यसभा में खड़गे-रिजिजू के बीच हुई तीखी नोकझोंक

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान शुक्रवार को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी और बयान देने की मांग को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री से सदन में आकर बयान देने की मांग की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि किसी विषय पर किस मंत्री को जवाब देना है, यह सरकार तय करती है, विपक्ष नहीं।

दरअसल, विपक्ष जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान 20 जुलाई को हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों पर अनावश्यक बल प्रयोग किया गया और इस पूरे मामले पर गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। उच्च सदन में खड़गे ने सभापति सीपी राधाकृष्णन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष पहले भी गृह मंत्री को सदन में बुलाने की मांग कर चुका है। उन्होंने कहा कि सभापति ने भी विपक्ष की भावना सरकार तक पहुंचाई थी, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। खड़गे ने इसे सदन की गरिमा और सभापति की भावना की अनदेखी बताया।

सरकार की ओर से जवाब देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि संसदीय परंपरा के अनुसार जिस विषय से संबंधित मंत्रालय होता है, उसी मंत्रालय का मंत्री सदन में जवाब देता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष यह निर्धारित नहीं कर सकता कि किसी मुद्दे पर कौन मंत्री सदन में उपस्थित होगा। रिजिजू ने यह भी कहा कि गृह मंत्री सुबह से देर रात तक संसद परिसर में मौजूद रहते हैं और सदन के कार्यों पर लगातार नजर रखते हैं।

रिजिजू ने स्पष्ट किया कि सभापति ने केवल विपक्ष की मांग सरकार तक पहुंचाई थी, किसी मंत्री को सदन में उपस्थित होने का निर्देश नहीं दिया था। उन्होंने विपक्ष पर हंगामा कर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप भी लगाया।

रिजिजू के वक्तव्य के दौरान विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध और नारेबाजी की, जिससे सदन का माहौल काफी गरमा गया। लगातार हंगामे के चलते सभापति ने पहले राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित की। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी गतिरोध कायम रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार, 10 अगस्त, सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मानसून सत्र में लगातार जारी इस गतिरोध के कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित होती रही है।

उत्तराखंड के टिहरी में लैंडस्लाइड, कांवड़िया बहा, चमोली में सड़क बंद

मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट किया जारी

देहरादून। उत्तराखंड में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश के बाद शुक्रवार को मौसम सामान्य है। ऋषिकेश में जल भरते समय दिल्ली से आया कांवड़िया बह गया, जिसे घाट पर तैनात एसडीआरएफ के हेड कांस्टेबल ने छलांग लगाकर बाहर निकाला। चमोली में लैंडस्लाइड से देवाल-वाण सड़क पिछले 24 घंटे से बंद है। रास्ते में मलबा आने के कारण पोकलैंड मशीन के बकेट में बैठाकर बच्चों को स्कूल पहुंचाया जा रहा है। टिहरी में सुबह दो जगह भूस्खलन हुआ। नरेंद्रनगर-रानीपोखरी और हिंडोलाखाल के पास पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर गिरने से सड़कें कुछ समय के लिए बंद रहीं, जिन्हें बाद में खोल दिया गया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी खतरे के निशाने से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में

बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी और बागेश्वर में कहीं-कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भी गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिर सकती है। खराब मौसम के चलते रुद्रप्रयाग में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं प्रदेश के 10 जिलों में 132 सड़कें बंद हैं। गंगोत्री हाईवे हेलगुगाड़, नालूपानी व गंगनानी के पास तथा यमुनोत्री हाईवे दुर्बिल व स्यानाचट्टी के पास मलबा आने से बंद था, जो अब खोल दिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक हरिद्वार के लक्सर में बालावाली गंगा का टूटा तटबंध अब 12 गांवों के लिए खतरा बना हुआ है। हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि और खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हैं। पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर मलघटिया के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण यातायात प्रभावित हुआ और यात्री फंस गए। टिहरी के घनसाली में भूस्खलन से एक कार मलबे में दब गई, जबकि आसपास के मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। हरिद्वार के ज्वालापुर में बारिश के दौरान एक विशाल पेड़ वाहनों पर गिर गया। लगातार बारिश से अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा, यमुना और शारदा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।

जालंधर के सबसे पुराने स्कूल में सिर्फ पांच टीचर ही बचे, भर्ती करे सरकार

जालंधर। पंजाब विधानसभा के चल रहे सत्र में जालंधर नॉर्थ और कैंट से विधायक बावा हैनरी और परगट सिंह ने सिटी के मुद्दे उठाए और इनके हल करने की मांग सदन में रखी।

बावा हैनरी ने बताया कि जालंधर के सबसे पुराने स्कूल साई दास में शिक्षा के हालात ये हैं कि यहां पांच शिक्षक रह गए हैं। सरकार यहां पर नए शिक्षकों की भर्ती करने की योजना बनाए। हैनरी ने कहा कि ये शहर का सबसे पुराना स्कूल है। इस स्कूल ने पंजाब और देश के विकास में अपना योगदान दिया है। इस स्कूल से करीब 97 स्टूडेंट्स आईएएस-पीसीएस अफसर बनकर निकले हैं।

बायोगैस उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

सरकार ने 10 गुना वृद्धि का बनाया रोडमैप

वेब वार्ता, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से बायोगैस उत्पादन को अगले दस वर्षों में 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय गोबरधन (गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही असम में एक महत्वपूर्ण चार लेन राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति मिली है। योजना के तहत कृषि अवशेष, गोबर, गन्ने के अपशिष्ट और अन्य जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे प्राकृतिक गैस के आयात में कमी आएगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।

सरकार ने शहरों में सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति करने वाली गैस वितरण कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से बायोगैस का मिश्रण करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2026-27 में 3 प्रतिशत, 2027-28 में 4 प्रतिशत और 2028-29 से 5 प्रतिशत सीबीजी मिश्रण अनिवार्य किया जाएगा।

प्रत्येक शुक्रवार को दौरे पर रहेंगे अधिकारी : मुख्यमंत्री

छिंदवाड़ा जिले में 1281 अधिकारी-कर्मचारियों को मिला पदोन्नति का लाभ

वेब वार्ता, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में सभी वर्गों के लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उनके नेतृत्व में दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अंत्योदय और जनकल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मध्यप्रदेश सरकार भी गरीब, किसान, युवा और नारी सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश में शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों की पदोन्नति वर्षों से अटकी थी। हमारी सरकार ने कर्मचारियों को पदोन्नति का उनका अधिकार दिलवाया। पदोन्नति के लिए सभी जरूरी प्रक्रियाओं को समय से पूरा करते हुए वर्तमान वर्ष में शेष रह गए अधिकारी-कर्मचारियों की भी पदोन्नति

17 हजार पदों पर नई भर्ती के लिए सूचना जारी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी विभागों में शासकीय पदों पर नई भर्तियों की शुरूआत कर दी है। पुलिस विभाग में ही 18 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। इसमें 1000 पद ड्राइवरों के भी शामिल हैं। स्कूल शिक्षकों के 10 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है। उच्च शिक्षा विभाग में 7 हजार से अधिक व्याख्याताओं की भर्ती की गई है। म.प्र. व्यावसायिक शिक्षा मंडल ने विभिन्न विभागों में 17 हजार पदों पर नई भर्ती के लिए सूचना जारी की है। बीते ढाई साल में एक लाख पदों पर भर्ती की जा चुकी है। अब 2 लाख नई भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है।

सितंबर-अक्टूबर माह में कर दी जाएगी। सरकार के कार्यों को धरातल पर सफल बनाने और सुशासन स्थापित करने में राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को छिंदवाड़ा के एफडीडीआई ऑडिटोरियम में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विकास और जनकल्याण के लिए राज्य सरकार दूरगामी विजन के साथ कार्य कर रही है। आज छिंदवाड़ा से एक नई शुरूआत की जा रही है। अब प्रत्येक शुक्रवार को किसी भी दफ्तर में कोई मीटिंग नहीं होगी। सभी अधिकारी जनता के बीच मौजूद रहकर मैदानी स्तर पर शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का जायजा लेंगे।

भारत को मजबूत सुरक्षा देतीं भारत की अग्नि-5, ब्रह्मोस, के-4 मिसाइलें, घबराते हैं दुश्मन

वेब वार्ता, नई दिल्ली

भारत की सुरक्षा व्यवस्था में मिसाइल तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की सैन्य गतिविधियों को देखते हुए भारत अपनी थल, जल और वायु सीमाओं को मजबूत करने पर लगातार काम कर रहा है।

इसी रणनीति के तहत देश ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और पनडुब्बी से दागी जाने वाली परमाणु सक्षम मिसाइलों का विकास किया है। अग्नि-5, ब्रह्मोस और के-4 ऐसी तीन मिसाइलें हैं, जो भारत की सामरिक क्षमता को नई मजबूती देती हैं।

अग्नि-5 परमाणु बेस मिसाइल

अग्नि-5 भारत की लंबी दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। यह करीब 5,000 से 5,800 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता एशिया के बड़े हिस्से के साथ यूरोप के कुछ क्षेत्रों तक पहुंचती है। लगभग 17.5 मीटर लंबी और करीब 50 टन वजनी यह मिसाइल तीन चरणों वाले ठोस ईंधन प्रणोदन सिस्टम से लैस है। इसमें आधुनिक नेविगेशन और स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे

इसकी सटीकता बढ़ती है। अग्नि-5 की सबसे बड़ी खासियत एमआईआरवी तकनीक है। इसके जरिए एक ही मिसाइल से कई परमाणु वॉरहेड अलग-अलग लक्ष्यों पर दागे जा सकते हैं। इस क्षमता के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास ऐसी उन्नत मिसाइल तकनीक मौजूद है। इसे सड़क और रेल आधारित मोबाइल लॉन्च सिस्टम से भी तैनात किया जा सकता है।

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से विकसित की गई है। यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में शामिल है और करीब मैक 2.8 से 3 की गति से लक्ष्य को निशाना बना सकती है। इसकी मारक क्षमता के नए संस्करणों में लगभग 400 से 800 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसे जमीन, युद्धपोत, पनडुब्बी और लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस की तेज रफ्तार, कम प्रतिक्रिया समय और सटीक वार करने की क्षमता इसे आधुनिक युद्ध के लिए बेहद प्रभावी हथियार बनाती है। भारत इसके और उन्नत संस्करणों पर भी काम कर रहा है, जिससे इसकी क्षमता भविष्य में और बढ़ सकती है।

के-4 मिसाइल, समुद्री ताकत

के-4 मिसाइल भारत की समुद्री परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे परमाणु हथियार ले जाने के लिए विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता करीब 3,500 किलोमीटर तक है और इसे अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों से लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है। के-4 की खासियत इसकी कोल्ड-लॉन्च तकनीक है, जिसमें मिसाइल पानी के दबाव से लॉन्च ट्यूब से बाहर निकलती है और बाद में इंजन सक्रिय होता है। इससे पनडुब्बी की सुरक्षा और संचालन क्षमता बेहतर होती है। यह भारत की न्यूक्लियर ट्रायड के समुद्री हिस्से को मजबूती देती है और देश की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाती है।

संपादकीय

एनटीए में सुधार

यह ठीक है कि बीते दिनों एनटीए के लिए अस्थायी रूप से काम करने वाले कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हटाया गया और उसके प्रशासनिक ढांचे को मजूबत बनाने के लिए महाप्रबंधक तथा उसके समकक्ष स्तर के पदों की भर्ती के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उचित यह होगा कि इन कदमों के संदर्भ में नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स से भी विचार-विमर्श किया जाए। और भी उचित यह होगा कि इस टास्क फोर्स को अपना काम शीघ्र शुरू करने को कहा जाए। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि यह टास्क फोर्स अपनी सिफारिशें कब तक देगा। इसके लिए कोई समयसीमा तय की जानी चाहिए। आवश्यक यह भी है कि उसकी ओर से जो सुझाव दिए जाएं, उन पर यथाशीघ्र अमल सुनिश्चित किया जाए। यह एक तथ्य है कि एनटीए के कामकाज में सुधार के लिए राधाकृष्णन समिति ने जो सुझाव दिए थे, उन सभी पर अमल नहीं किया गया।

मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की परीक्षा नीट के पेपर लीक होने के बाद इसे आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कामकाज में सुधार किया जाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गया है।

इसी तरह शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की सिफारिशों पर भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। शायद इस सबका ही परिणाम यह रहा कि एनटीए नीट के साथ अन्य केंद्रीय परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने में नाकाम रही। इसी नाकामी का नतीजा छात्रों के उस आंदोलन के रूप में सामने आया, जिसके चलते शिक्षा मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। इस त्यागपत्र के बाद पेपर लीक रोधी कानून में संशोधन कर उसे और कठोर भी बनाया गया। निःसंदेह परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले तत्वों को हतोत्साहित करने के लिए संबंधित कानून को कठोर करना ही चाहिए, क्योंकि देश में एक पेपर लीक माफिया पैदा हो गया है, लेकिन इसी के साथ इसके उपाय भी करने चाहिए, जिससे पेपर लीक ही न हो सके। ऐसा तब होगा, जब एनटीए और इस जैसी अन्य संस्थाओं की कार्यप्रणाली में अपेक्षित बदलाव होंगे।

यह साधारण बात नहीं कि पिछले कुछ समय से प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ स्कूली परीक्षाओं में भी सेंध लग रही है। इसे देखते हुए परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को न केवल उन्नत तकनीक को अपनाना चाहिए, बल्कि प्रश्नपत्रों के कई सेट तैयार करने जैसे कदम भी उठाने चाहिए। नीट जैसी जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों छात्र बैठते हैं, उन्हें वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित करने पर विचार किया जाना चाहिए। आवश्यक केवल यह नहीं है कि एनटीए की कार्यप्रणाली सुधरे, बल्कि यह भी है कि किसी भी स्तर की परीक्षाएं आयोजित कराने वाली संस्थाओं का कामकाज ऐसा हो कि परीक्षार्थियों के मन में परीक्षाओं की शुचिता को लेकर कोई संदेह न रहे।

संसद में गतिरोध और लोकतंत्र : संवाद की संस्कृति कब लौटेगी ?

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संसद है। संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि देश की जनता की आकांक्षाओं, समस्याओं और भविष्य की दिशा तय करने वाला सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्थान है। यहां सत्ता और विपक्ष दोनों जनता के प्रतिनिधि के रूप में बैठते हैं। सत्ता पक्ष सरकार चलाने के लिए जनादेश लेकर आता है, जबकि विपक्ष सरकार की नीतियों की समीक्षा, आलोचना और आवश्यक सुधारों का सुझाव देने की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाता है। जब संसद सुचारु रूप से चलती है, तब लोकतंत्र मजबूत होता है; लेकिन जब संसद लगातार गतिरोध का शिकार होती है, तब केवल सदन का समय ही नष्ट नहीं होता, बल्कि जनता का विश्वास भी कमजोर होने लगता है।

हाल के वर्षों में संसद के प्रत्येक सत्र में किसी न किसी मुद्दे को लेकर गतिरोध देखने को मिलता है। कभी विपक्ष सरकार से किसी विषय पर चर्चा की मांग करता है, तो कभी सरकार विपक्ष पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाती है। परिणाम यह होता है कि प्रश्नकाल स्थगित हो जाता है, विधेयक बिना व्यापक बहस के पारित हो जाते हैं और जनता के करोड़ों रुपये का समय और संसाधन व्यर्थ चला जाता है। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन मतभेद यदि संवाद के स्थान पर टकराव का रूप ले लें, तो लोकतंत्र की आत्मा आहत होती है। संसद में हंगामा कोई नई बात नहीं है। भारतीय संसदीय इतिहास में कई बार तीखी बहसें हुई हैं, विरोध प्रदर्शन हुए हैं और सदन की कार्यवाही बाधित भी हुई है। किंतु अतीत में लंबे और गंभीर विमर्श भी होते थे। विपक्ष सरकार को कठघरे में खड़ा करता था, सरकार जवाब देती थी और अंततः जनता के सामने तथ्य आते थे। आज स्थिति यह है कि बहस की जगह नारेबाजी और संवाद की जगह राजनीतिक रणनीति ने ले ली है। इससे संसद की गरिमा प्रभावित होती है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष केवल सरकार का विरोध करने के लिए नहीं होता, बल्कि वह वैकल्पिक सोच प्रस्तुत करता है। यदि सरकार कोई गलत निर्णय लेती है तो उसे रोकना, जनता की समस्याओं को सदन में उठाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना विपक्ष का दायित्व है। दूसरी ओर सरकार का दायित्व है कि वह विपक्ष की बात सुने, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराए और संसद को विश्वास में लेकर आगे बढ़े। यदि दोनों पक्ष अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का संतुलन खो देते हैं, तो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। आज संसद में अनेक महत्वपूर्ण विषय चर्चा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा विवाद, डिजिटल अपराध, पर्यावरण संरक्षण, न्यायिक सुधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियां तथा आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे व्यापक बहस की मांग करते हैं। दुर्भाग्य यह है कि इन विषयों पर गंभीर चर्चा कम और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप अधिक दिखाई देते हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों को नारे लगाने के लिए नहीं, बल्कि समाधान खोजने के लिए संसद भेजती है।

संसदीय परंपराओं का सम्मान लोकतंत्र की मजबूती की पहली शर्त है। संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण आज करोड़ों लोग देखते हैं। युवा पीढ़ी अपने जनप्रतिनिधियों से सीखती है कि लोकतंत्र में असहमति कैसे व्यक्त की जाती है। यदि संसद में लगातार शोर-शराबा, नारेबाजी और अव्यवस्था दिखाई देगी, तो समाज में भी संवाद की संस्कृति कमजोर होगी। लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुमत नहीं, बल्कि असहमति का सम्मान भी है। एक गंभीर प्रश्न यह भी है कि संसद का बहुमूल्य समय बार-बार नष्ट होने की कीमत कौन चुकाता है? संसद चलाने में प्रतिदिन करोड़ों रुपये का खर्च आता है। यह धन करदाताओं की मेहनत की कमाई है। जब सदन की कार्यवाही बिना किसी सार्थक चर्चा के स्थगित हो जाती है, तब यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही का भी नुकसान होता है। जनता यह अपेक्षा करती है कि उसके प्रतिनिधि हर मिनट का उपयोग उसके हित में करें। विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा लोकतंत्र की मूल आवश्यकता है। किसी भी कानून का प्रभाव वर्षों तक समाज पर पड़ता है। यदि विधेयक बिना पर्याप्त बहस के पारित हो जाएं, तो भविष्य में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया जितनी पारदर्शी और विचारपूर्ण होगी, कानून उतने ही प्रभावी और स्वीकार्य होंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह महत्वपूर्ण विधेयकों पर विपक्ष को पर्याप्त समय दे और विपक्ष को भी रचनात्मक सुझावों के साथ बहस में भाग लेना चाहिए।

मीडिया की भूमिका भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यदि मीडिया केवल राजनीतिक टकराव को प्रमुखता देगा और गंभीर संसदीय बहसों को पर्याप्त स्थान नहीं देगा, तो राजनीतिक दल भी सुर्खियां बटोरने वाली राजनीति को प्राथमिकता देंगे। लोकतंत्र में मीडिया का दायित्व केवल विवाद दिखाना नहीं, बल्कि नीति, कानून और जनहित के मुद्दों पर सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना भी है। संसद में गतिरोध का एक कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण भी है। आज राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक मतभेद स्वाभाविक सीमा से आगे बढ़कर व्यक्तिगत और स्थायी विरोध का रूप लेते दिखाई देते हैं। लोकतंत्र में चुनावी प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए। संसद में सत्ता और विपक्ष प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, शत्रु नहीं। यदि यह भावना विकसित हो जाए कि देश पहले और राजनीति बाद में, तो अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः संभव हो जाएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अनेक विकासशील देश भारत की संसदीय व्यवस्था को आदर्श मानते हैं। ऐसे में हमारी संसद का आचरण केवल देश के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व समुदाय के लिए भी संदेश देता है। यदि संसद निरंतर गतिरोध का प्रतीक बनेगी, तो यह भारत की लोकतांत्रिक छवि को भी प्रभावित करेगा। इसलिए प्रत्येक सांसद की जिम्मेदारी व्यक्तिगत और दलगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय दायित्व निभाने की है। संसद को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक सुधारों पर भी विचार किया जाना चाहिए। सभी दलों के बीच नियमित सर्वदलीय बैठकें हों, विवादित विषयों पर पहले से सहमति बनाने का प्रयास हो, संसदीय समितियों को और अधिक सशक्त बनाया जाए तथा प्रश्नकाल और शून्यकाल की गरिमा को हर परिस्थिति में बनाए रखा जाए। साथ ही, बार-बार सदन की कार्यवाही बाधित करने वाले सदस्यों के विरुद्ध संसदीय नियमों के अनुरूप निष्पक्ष कार्रवाई भी आवश्यक है। नियमों का पालन सत्ता और विपक्ष—दोनों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि सांसद स्वयं को केवल राजनीतिक दल का प्रतिनिधि न मानें, बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि समझें। उनके निर्वाचन क्षेत्र के नागरिक यह जानना चाहते हैं कि संसद में उनके प्रतिनिधि ने कितने प्रश्न पूछे, किन मुद्दों पर चर्चा की, कितनी समितियों में भाग लिया और क्षेत्र के विकास के लिए क्या प्रयास किए। लोकतंत्र में जनता की यह निगरानी भी संसद की कार्यक्षमता बढ़ा सकती है। भारतीय संविधान ने संसद को सर्वोच्च विधायी संस्था का दर्जा दिया है। संविधान निमार्ताओं ने यह कल्पना नहीं की थी कि संसद लगातार गतिरोध का मंच बन जाएगी। उन्होंने ऐसी संसद की परिकल्पना की थी, जहां तर्क, तथ्य, शालीनता और संवैधानिक मयार्दा सर्वोच्च हों। डॉ. भीमराव आंबेडकर सहित संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने लोकतंत्र में संवैधानिक नैतिकता और संस्थागत मयार्दा के महत्व पर विशेष बल दिया था। आज उन आदर्शों को पुनः स्मरण करने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष को यह समझना होगा कि बहुमत संवाद का विकल्प नहीं हो सकता। विपक्ष की बात सुनना लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत है। वहीं विपक्ष को भी यह स्वीकार करना होगा कि विरोध का उद्देश्य संसद को ठप करना नहीं, बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाना होना चाहिए। विरोध तब सबसे प्रभावी होता है, जब वह तथ्यों, तर्कों और जनहित के आधार पर किया जाए। जनता भी इस पूरी प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण भागीदार है। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों से प्रश्न पूछने चाहिए, उनके संसदीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना चाहिए और केवल राजनीतिक नारों के बजाय नीति आधारित राजनीति को प्रोत्साहित करना चाहिए। जब मतदाता विकास, बहस और जवाबदेही को प्राथमिकता देंगे, तब राजनीतिक दल भी अपनी रणनीति बदलने के लिए विवश होंगे।

आज आवश्यकता इस बात की है कि संसद फिर से विचारों के महाकुंभ के रूप में स्थापित हो। जहां असहमति हो, लेकिन कटुता न हो; जहां विरोध हो, लेकिन अवरोध न हो; जहां सत्ता जवाब दे और विपक्ष समाधान प्रस्तुत करे; जहां कानून जल्दबाजी में नहीं, बल्कि व्यापक विमर्श के बाद बनें। यही लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है।

संसद का गतिरोध किसी एक दल की नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की चिंता है। संसद जितनी प्रभावी होगी, लोकतंत्र उतना ही सशक्त होगा। सत्ता और विपक्ष दोनों को यह स्मरण रखना चाहिए कि वे अंततः जनता के सेवक हैं, प्रतिद्वंद्वी अवश्य हैं पर लोकतंत्र के साझेदार भी हैं। भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को नई ऊर्जा तभी मिलेगी, जब संसद में शोर नहीं, संवाद होगा; टकराव नहीं, समाधान होगा; और राजनीतिक लाभ से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा। यही लोकतंत्र की गरिमा है और यही संसद की वास्तविक पहचान भी होनी चाहिए।

सौरभ वार्ष्णेय
लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।

अहिंसा कायरता नहीं बल्कि मानवता का उज्ज्वल प्रतीक है

अहिंसा भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह केवल हिंसा का अभाव नहीं बल्कि प्रेम करुणा दया सहिष्णुता और आत्मबल का ऐसा महान संदेश है जो मानव जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। अहिंसा मनुष्य को दुर्बल नहीं बनाती बल्कि उसके भीतर साहस संयम और आत्मविश्वास का संचार करती है। यही कारण है कि भारतीय मनीषियों ने अहिंसा को धर्म का सर्वोच्च स्वरूप माना है। अहिंसा का अर्थ किसी भी जीव को मन वचन और कर्म से कष्ट न पहुंचाना है। यह केवल व्यक्तिगत आचरण तक सीमित नहीं रहती बल्कि परिवार समाज राष्ट्र और पूरे विश्व को शांति और सद्भाव का मार्ग दिखाती है।

अहिंसा की दृष्टि अत्यंत व्यापक और विराट है। इसमें संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। यह किसी जाति धर्म भाषा प्रदेश अथवा संप्रदाय की सीमाओं में बंधी हुई विचारधारा नहीं है। जिस प्रकार गंगा का निर्मल जल सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध रहता है उसी प्रकार अहिंसा भी संपूर्ण मानवता के लिए समान रूप से उपयोगी है। यदि इसे किसी विशेष वर्ग या समुदाय तक सीमित कर दिया जाए तो इसका वास्तविक स्वरूप नष्ट हो जाएगा। अहिंसा का संदेश समस्त विश्व के लिए है और इसकी शक्ति किसी भी हथियार से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि अहिंसा ने अनेक बार असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को संभव बनाया है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजी शासन जैसी विशाल शक्ति को चुनौती दी। उन्होंने न तो हथियार उठाए और न ही हिंसा का सहारा लिया। फिर भी सत्याग्रह असहयोग आंदोलन और दांडी यात्रा जैसे आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया। करोड़ों भारतीयों की नैतिक शक्ति के सामने अंग्रेजी साम्राज्य को झुकना पड़ा। यह सिद्ध हो गया कि आत्मबल और सत्य पर आधारित अहिंसा किसी भी सैन्य शक्ति से अधिक प्रभावशाली हो सकती है।

अहिंसा का अर्थ कभी भी कायरता नहीं होता। कायर व्यक्ति भय के कारण संघर्ष से बचता है जबकि अहिंसक व्यक्ति अन्याय का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करता है। अहिंसा वीरों का धर्म है क्योंकि इसके लिए अत्यंत धैर्य त्याग और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति क्रोध और प्रतिशोध की भावना पर विजय प्राप्त कर लेता है वही वास्तविक अर्थों में वीर कहलाता है। हिंसा करना सरल हो सकता है किंतु क्षमा करना और शांति बनाए रखना कहीं अधिक कठिन है। इसलिए अहिंसा दुर्बलों का नहीं बल्कि आत्मबल से परिपूर्ण व्यक्तियों का मार्ग है।

अहिंसा मनुष्य को यह शिक्षा देती है कि वह अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे के अधिकारों का हनन न करे। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी समाज या राष्ट्र के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विवाद चाहे व्यक्तिगत हो या अंतरराष्ट्रीय उसका समाधान संवाद समझदारी और शांतिपूर्ण प्रयासों से खोजा जाना चाहिए। यदि शांति स्थापित करने के लिए त्याग और बलिदान देना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। यही सच्ची अहिंसा का स्वरूप है।

यह भी सत्य है कि अहिंसा अन्याय को सहन करने की शिक्षा नहीं देती। अन्याय करना जितना बड़ा अपराध है उतना ही बड़ा अपराध अन्याय को कायरता के कारण स्वीकार कर लेना भी है। यदि किसी व्यक्ति समाज या राष्ट्र पर अत्याचार हो रहा हो तो उसका प्रतिकार करना आवश्यक है। अहिंसा का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अन्याय के सामने हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे। यदि देश धर्म समाज और मानवता की रक्षा के लिए आवश्यक हो तो साहसपूर्ण कदम उठाना भी कर्तव्य बन जाता है। इसलिए अहिंसा विवेकपूर्ण साहस का मार्ग है न कि निष्क्रियता का। भारतीय संतों और महापुरुषों ने अपने जीवन से अहिंसा की महानता को सिद्ध किया है। भगवान महावीर ने संपूर्ण जीवन अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने प्रत्येक जीव में आत्मा का वास माना और सभी के प्रति दया का व्यवहार करने की प्रेरणा दी। उनके विचार आज भी विश्वभर में शांति और सहअस्तित्व की भावना को मजबूत करते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी प्रेम करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश देकर समाज की अनेक बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने हिंसा और घृणा के स्थान पर मैत्री और करुणा को अपनाने की शिक्षा दी। उनके उपदेश आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं।

ईसा मसीह ने भी प्रेम और क्षमा की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की। उन्होंने अपने विरोधियों तक के लिए क्षमा का भाव रखा और यह संदेश दिया कि यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। इस शिक्षा का वास्तविक अर्थ कायरता नहीं बल्कि घृणा का उत्तर प्रेम से देना है। यह मनुष्य के भीतर की महानता को प्रकट करता है और समाज में वैमनस्य के स्थान पर सद्भाव को बढ़ावा देता है।

आधुनिक युग में जब संसार युद्ध आतंकवाद हिंसा और कट्टरता जैसी समस्याओं से जूझ रहा है तब अहिंसा की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। आज विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को सुविधाजनक तो बनाया है किंतु साथ ही विनाशकारी हथियारों का भी निर्माण किया है। ऐसे समय में यदि विश्व को स्थायी शांति चाहिए तो उसे अहिंसा सहिष्णुता और संवाद की राह अपनानी होगी। परिवार से लेकर अंतरराष्ट्रीय संबंधों तक हर स्तर पर प्रेम विश्वास और सहयोग की भावना विकसित करनी होगी।

अहिंसा केवल युद्ध न करने का नाम नहीं है बल्कि अपने व्यवहार विचार और वाणी में भी शालीनता बनाए रखना है। कटु शब्द भी हिंसा का रूप होते हैं और मधुर वचन भी अहिंसा की अभिव्यक्ति बन सकते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर से घृणा ईर्ष्या और द्वेष को समाप्त कर देता है तब उसके जीवन में शांति और संतोष का उदय होता है। यही शांति समाज और राष्ट्र तक पहुंचकर विश्व शांति का आधार बनती है।

अंततः कहा जा सकता है कि अहिंसा मानव सभ्यता की सबसे महान उपलब्धियों में से एक है। यह कायरता नहीं बल्कि आत्मबल सत्य साहस और मानवता का उज्ज्वल प्रतीक है। अहिंसा हमें न्याय के लिए संघर्ष करना सिखाती है किंतु घृणा और प्रतिशोध के बिना। यह प्रेम करुणा और क्षमा के माध्यम से समाज को जोड़ने का कार्य करती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसा के आदर्शों को अपनाए तो विश्व में शांति सद्भाव और भाईचारे की स्थापना संभव है। यही वह मार्ग है जो मानवता को विनाश से बचाकर विकास समृद्धि और स्थायी शांति की ओर ले जा सकता है।

कांतिलाल मांडोत

मुआवजे में उलझ कर रह गई विकास की राह

गांव तक सड़क पहुंचना केवल विकास की एक परियोजना नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षित आवागमन तक पहुंच का रास्ता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य भी ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में चलने योग्य सड़कों से जोड़ना है। बिहार में इस दिशा में लंबे समय से काम हुआ है और बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी हुआ है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बिहार में इसके तहत 52,095.37 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हो चुका था, जबकि 3,439.10 किलोमीटर सड़क निमार्णाधीन थी. ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य में ग्रामीण सड़क संपर्क के विस्तार की दिशा में व्यापक काम हुआ है, लेकिन किसी योजना की सफलता का आकलन केवल किलोमीटर में बनी सड़कों से नहीं किया जा सकता। असली सवाल यह है कि क्या सड़क आखिरी घर तक पहुंची है और क्या वह पूरे साल लोगों के उपयोग के लायक है।

राज्य के कुछ गांव ऐसे हैं जहां आज भी पक्की सड़क गांव के भीतर तक नहीं पहुंच सकी है। इसके पीछे हर बार प्रशासनिक उदासीनता या बजट की कमी ही जिम्मेदार हो, यह जरूरी नहीं। कई बार विकास और निजी जमीन के अधिकार के बीच पैदा हुआ विवाद भी सड़क को रोक देता है। सीतामढ़ी के ललितपुर गांव की स्थिति इसी जटिलता की ओर इशारा करती है। इस गांव के अंदर पक्की सड़क पहुंचाने की राह में कुछ लोगों की निजी जमीन आ रही है। सरकार की ओर से जमीन के बदले मुआवजा देने की व्यवस्था है, लेकिन जमीन मालिकों का कहना है कि उन्हें मिलने वाला मुआवजा जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य की तुलना में कम है। इसी असहमति के कारण वे सड़क निर्माण के लिए अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं।

पक्की सड़क न होने का सबसे बड़ा असर बारिश के दिनों में दिखाई देता है। कच्चे रास्ते पर पानी और कीचड़ जमा होने के बाद पैदल चलना भी कठिन हो जाता है। ऐसे समय में एम्बुलेंस या दूसरी गाड़ियों का गांव के अंदर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बीमारी या प्रसव जैसी आपात स्थिति में यह समस्या परिवार के लिए गंभीर संकट बन सकती है। सड़क की कमी का असर केवल मरीज तक सीमित नहीं रहता। परिवार के किसी सदस्य को उसे मुख्य सड़क तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त समय और श्रम लगाना पड़ सकता है।

सड़क की समस्या का एक और कम दिखाई देने वाला असर किशोरियों की शिक्षा पर पड़ता है। गांव की किशोरियों के लिए स्कूल तक पहुंचना केवल दूरी का मामला नहीं है। रास्ते की स्थिति, मौसम, परिवहन की उपलब्धता और परिवार की सुरक्षा संबंधी चिंता भी उनकी नियमित पढ़ाई को प्रभावित करती है। जब रास्ता खराब होता है तो स्कूल जाने और लौटने में अधिक समय लगता है। बारिश में कीचड़ और जलभराव के कारण अकेले निकलना कठिन हो जाता है। परिवार कई बार किशोरी को ऐसे रास्ते से भेजने में हिचकिचाता है, खासकर तब जब स्कूल गांव से बाहर हो। नतीजा यह हो सकता है कि कुछ दिनों की अनुपस्थिति धीरे-धीरे पढ़ाई से दूरी में बदल जाए।

यह समस्या इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण किशोरियों के लिए शिक्षा का हर अतिरिक्त वर्ष उनके भविष्य के विकल्पों को बढ़ाता है। स्कूल तक पहुंचने में कठिनाई केवल आज की परेशानी नहीं है। इसका संबंध आगे की पढ़ाई, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी से भी है। जब खराब सड़क के कारण किसी किशोरी की आवाजाही सीमित होती है, तो उसके अवसर भी सीमित हो सकते हैं। दूसरी ओर गांव में बेहतर सड़क होने पर स्कूल, बाजार, स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच आसान होती है। इससे परिवारों को भी किशोरियों की शिक्षा जारी रखने का अधिक भरोसा मिलता है।

वास्तव में, जमीन किसी ग्रामीण परिवार के लिए सिर्फ संपत्ति ही नहीं होती है बल्कि वह उसकी आजीविका, भविष्य की सुरक्षा और कई बार पीढ़ियों से जुड़ी पूंजी होती है। इसलिए उचित मुआवजे की मांग को नजरअंदाज करके सड़क निर्माण का समाधान संभव नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि कुछ परिवारों की जमीन से जुड़ा विवाद पूरे गांव की बड़ी आबादी को बुनियादी सुविधा से वंचित न कर दे। इसलिए ललितपुर का विवाद केवल ह्यसड़क बनाम जमीनह्ण का विवाद नहीं माना जाना चाहिए। इसे इस सवाल के रूप में भी देखना चाहिए कि विकास का लाभ किस तरह सभी तक पहुंचे और जमीन देने वाले परिवार के साथ न्याय भी हो।

समाधान बातचीत और भरोसे से निकल सकता है, टकराव से नहीं। प्रशासन को जमीन मालिकों, पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणों और सड़क निर्माण से जुड़े अधिकारियों की संयुक्त बैठक कराकर विवाद का समाधान तलाशना चाहिए। जहां संभव हो, सड़क की ऐसी वैकल्पिक रूपरेखा पर भी विचार किया जा सकता है जिससे कम से कम निजी जमीन प्रभावित हो। लेकिन यदि जमीन लेना अपरिहार्य हो, तो मुआवजे को लेकर उठे सवालों का निष्पक्ष समाधान जरूरी है। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल सड़क का निर्माण पूरा दिखाने के लिए कागजों पर समाधान न हो, बल्कि गांव के अंतिम हिस्से तक वास्तविक, टिकाऊ और हर मौसम में उपयोगी सड़क पहुंचे।

ग्रामीण विकास की असली परीक्षा यही है कि योजना की पहुंच वहां तक हो जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सड़क केवल मिट्टी, गिट्टी और डामर से नहीं बनती। उसके रास्ते में लोगों के अधिकार, उनकी आजीविका और पूरे समुदाय की जरूरतें भी होती हैं। इसलिए सरकार और ग्रामीणों दोनों को अपने-अपने पक्ष से आगे बढ़कर साझा समाधान तलाशना होगा। जमीन का उचित मूल्य मिलना ग्रामीण का अधिकार है और सड़क से जुड़ना पूरे गांव की जरूरत। इन दोनों के बीच ऐसा रास्ता निकालना ही सबसे टिकाऊ समाधान होगा।

अंकि कुमारी, सीतामढ़ी, बिहार

यूजीसी नियमों का विवाद

करणी सेना का आंदोलन और राजस्थान की चुनावी राजनीति

राजस्थान की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां शिक्षा से जुड़ा एक प्रशासनिक और कानूनी मुद्दा अब सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से अधिसूचित नए नियमों के विरोध में श्री राजपूत करणी सेना और अन्य सवर्ण संगठनों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। जयपुर में निकाले गए विरोध मार्च के दौरान पुलिस लाठीचार्ज, एक प्रदर्शनकारी की मौत के आरोप और उसके बाद उपजे आक्रोश ने इस विवाद को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब राजस्थान में पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनाव निकट हैं। इसलिए इस आंदोलन को केवल एक शैक्षणिक नीति के विरोध तक सीमित नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसके राजनीतिक प्रभावों पर भी व्यापक चर्चा हो रही है।

यूजीसी ने नए नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकना तथा उन्हें सुरक्षित और समान वातावरण उपलब्ध कराना बताया था। आयोग का तर्क था कि उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से मौजूद व्यवस्था को अधिक प्रभावी और कठोर बनाया जाना आवश्यक है। इसी सोच के साथ नए नियम अधिसूचित किए गए।

हालांकि इन नियमों को अधिसूचित किए जाने के तुरंत बाद कई पक्षों ने इन्हें चुनौती दी और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। जनवरी 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने इन नियमों के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। वर्तमान में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वर्ष 2012 के पुराने नियम ही लागू हैं। इसके बावजूद करणी सेना और अन्य सवर्ण संगठनों का कहना है कि केवल न्यायालय की अंतरिम रोक पर्याप्त नहीं है। उनका तर्क है कि यदि भविष्य में न्यायालय यह रोक हटा देता है तो ये नियम स्वतः प्रभावी हो जाएंगे। इसलिए उनकी मांग है कि सरकार स्वयं इन नियमों को पूरी तरह वापस ले।

विरोध करने वाले संगठनों की मुख्य आपत्ति यह है कि नए नियमों में शिकायत दर्ज होते ही सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना अधिक है और झूठी अथवा दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से बचाव के पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं। उनका कहना है कि यदि किसी छात्र पर बिना निष्पक्ष जांच के कार्रवाई होती है और उसके प्रवेश, पढ़ाई या भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा। साथ ही उनका यह भी आरोप है कि झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसी आधार पर करणी सेना ने इन नियमों की तुलना अंग्रेजों के दौर के रोलेट एक्ट से करते हुए कहा कि इसमें आरोपित व्यक्ति को पर्याप्त अवसर नहीं मिलता।

दूसरी ओर, इन नियमों के समर्थकों का मानना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना राज्य और संस्थानों की जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि यदि भेदभाव की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम नहीं होंगे तो समान अवसर और सामाजिक न्याय का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इस प्रकार यह विवाद केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण और अधिकारों की अलग-अलग व्याख्याओं का भी विषय बन गया है।

जयपुर में करणी सेना द्वारा निकाले गए विरोध मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव ने इस पूरे आंदोलन को नया मोड़ दे दिया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और उसके बाद एक कार्यकर्ता देवराज सिंह पलाड़ा की अस्पताल में मृत्यु की खबर सामने आई। आंदोलनकारी संगठनों ने इसे प्रशासनिक कार्रवाई से जोड़ते हुए सरकार के खिलाफ तीखा विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद जयपुर बंद, मुख्यमंत्री आवास के घेराव और राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इस घटना ने आंदोलन को केवल यूजीसी नियमों तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे सरकार के प्रति असंतोष के रूप में भी प्रस्तुत किया जाने लगा।

राजस्थान की राजनीति में सवर्ण समाज, विशेष रूप से राजपूत समुदाय, लंबे समय से प्रभावशाली भूमिका निभाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी को परंपरागत रूप से इस वर्ग का महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त होता रहा है। ऐसे में यदि इस वर्ग में असंतोष बढ़ता है तो उसका असर पंचायत और निकाय चुनावों पर पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय चुनावों में सामाजिक समीकरण अधिक प्रभावी होते हैं और ऐसे मुद्दे मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं।

राजनीतिक जानकार इस घटनाक्रम की तुलना पूर्व में आनंदपाल एनकाउंटर के बाद उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों से भी कर रहे हैं, जब राजपूत समाज के एक हिस्से में सरकार के प्रति नाराजगी देखने को मिली थी। उस समय भी यह माना गया था कि यदि समय रहते संवाद और विश्वास बहाली के प्रयास नहीं किए गए तो राजनीतिक नुकसान हो सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में भी कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ संवाद स्थापित करने की होगी।

इस आंदोलन की टाइमिंग भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दिल्ली में हाल के छात्र आंदोलनों के बाद अब यूजीसी नियमों को लेकर राजस्थान में आंदोलन तेज होना कई राजनीतिक संकेत देता है। करणी सेना ने इस मुद्दे को केवल एक संगठनात्मक अभियान नहीं रहने दिया, बल्कि इसे सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के अधिकारों और भविष्य से जोड़कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि यह अभियान अन्य राज्यों में भी गति पकड़ता है तो यह राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक विमर्श का विषय बन सकता है।

करणी सेना की मांग है कि यूजीसी के नए नियम पूरी तरह वापस लिए जाएं, जातीय उत्पीड़न की शिकायतों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए, झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ भी समान रूप से कठोर कार्रवाई का प्रावधान हो तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के अधिकारों और संरक्षण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएं। दूसरी ओर सरकार और न्यायपालिका के सामने चुनौती यह है कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और निष्पक्ष प्रक्रिया—इन तीनों के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए।

फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय की अंतरिम रोक के कारण नए नियम लागू नहीं हैं, लेकिन आंदोलन जारी है। इससे स्पष्ट है कि यह विवाद केवल कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक विश्वास, राजनीतिक रणनीति और चुनावी समीकरणों से भी जुड़ चुका है। आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों में यह मुद्दा किस सीमा तक मतदाताओं को प्रभावित करेगा, यह भविष्य के राजनीतिक घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। इतना अवश्य है कि राजस्थान की राजनीति में यूजीसी नियमों का यह विवाद अब केवल शिक्षा का विषय नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता, राजनीतिक संदेश और चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

-कांतिलाल मांडोत

संक्षिप्त वार्ता

बारिश में जलमग्न हुआ बुराड़ी, आदेश भारद्वाज ने सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली, 07 अगस्त (वेब वार्ता)। बुराड़ी क्षेत्र में हल्की बारिश के बाद जलभराव और टूटी सड़कों की समस्या को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं करावल नगर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष आदेश भारद्वाज ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नालों की समुचित सफाई नहीं होने से हर वर्ष बारिश के दौरान लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आदेश भारद्वाज ने कहा कि जलभराव के कारण बुराड़ी, नत्थूपुरा, इब्राहिमपुर, कौशिक एन्क्लेव और अमृत विहार जैसे क्षेत्रों का संपर्क राजधानी के अन्य हिस्सों से प्रभावित हो जाता है। उनका दावा है कि डीटीसी बसों सहित अन्य वाहनों का संचालन बाधित हो जाता है, जबकि स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

यमुना की सफाई पर सरकार को घेरा, विपिन शर्मा ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, 07 अगस्त (वेब वार्ता)। पूर्व विधायक विपिन शर्मा ने यमुना नदी की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यमुना की सफाई के दावे धरातल पर सफल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय बाद भी नदी की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।

विपिन शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने का वादा किया गया था, लेकिन मानसून के मौसम में भी नदी प्रदूषित दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि राजधानी से गुजरने वाले यमुना के हिस्से में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता का विषय बना हुआ है और इससे नदी का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा है।

मनोज कुमार द्विवेदी ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभाला

नई दिल्ली, 07 अगस्त (वेब वार्ता)। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनोज कुमार द्विवेदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं और नागरिक सेवाओं की समीक्षा की।

बैठक में मनोज कुमार द्विवेदी ने प्रभावी सेवा वितरण, बेहतर समन्वय और नागरिक-केंद्रित कार्यप्रणाली पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि परिषद की प्राथमिकता राजधानी क्षेत्र में जनसुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करना होगी।

डाबर के उत्पादों पर एफएसएसएआई के प्रतिबंध पर हाईकोर्ट की रोक

नई दिल्ली, 07 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को डाबर इंडिया के शहद, घी, नारियल तेल समेत कई उत्पादों पर 100% शुद्ध, 100% प्राकृतिक और 100% ऑर्गेनिक जैसे दावों के साथ बिक्री रोकने के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने डाबर की याचिका पर सुनवाई करते हुए एफएसएसएआई के 3 अगस्त के प्रतिबंधात्मक आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है।

दिल्ली में मानसून सीजन में जलभराव के स्थान घटे

उपराज्यपाल की समीक्षा बैठक में दिल्ली यातायात पुलिस ने दावा किया

वेब वार्ता, नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में मानसून के दौरान जलभराव और यातायात जाम में कमी दर्ज की गई है। दिल्ली यातायात पुलिस ने उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू की समीक्षा बैठक में यह दावा करते हुए बताया कि मानसून में जलभराव वाले स्थान 169 से घटकर 65 रह गए हैं। वहीं बार-बार जलभराव वाले स्थानों की संख्या 53 से घटकर इस वर्ष केवल 20 रह गई है।

पुलिस आयुक्त के साथ विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात), संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) और सभी रेंज के उप पुलिस आयुक्त (यातायात) बैठक में शामिल हुए। इन्होंने उपराज्यपाल को बताया कि वर्ष 2025 में जलभराव वाले 169 स्थान चिह्नित हुए थे। वर्ष 2024 में ऐसे 194 स्थान थे। इस मानसून सीजन में लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग समेत सभी एजेंसियों के सक्रिय प्रयासों से जलभराव कम होने से राहत मिली है। यातायात पुलिस ने बताया कि जलभराव कम होने से यातायात भी कम प्रभावित हुआ। इस बार जुलाई में यातायात संबंधी 572 कॉल हेल्पलाइन पर प्राप्त हुईं। पिछले वर्ष इसी माह में 701 कॉल आई थीं। इसी तरह सोशल मीडिया शिकायतें 1792 से घटकर 1653 हो गईं।

प्रोजेक्ट संगम से यातायात सुधार

दिल्ली यातायात पुलिस ने ह्यप्रोजेक्ट संगमह्ल से यातायात सुधार होने का दावा भी किया। उराज्यपाल को बताया गया कि इस अभियान के तहत रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और बाजार कल्याण संघों (एमडब्ल्यूए) के साथ 553 संयुक्त बैठकों में यातायात संबंधी 510 शिकायतें मिलीं, जिसमें से 410 का समाधान किया जा चुका है। शेष 100 शिकायतें नागरिक एजेंसियों को भेजी गई हैं। इसके अलावा ह्यट्रैफिक पाठशालाह्ल पहल के तहत 710 प्रमुख चौराहों पर 17400 से अधिक उल्लंघनकताओं को सड़क सुरक्षा संबंधी परामर्श दिया गया।

गूगल मैप्स और मैप माई इंडिया पर मिलेगा ट्रैफिक का रियल टाइम अलर्ट

उपराज्यपाल ने कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस के लिए विशेष यातायात व्यवस्था और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की। इसमें बताया गया कि गूगल मैप्स और मैप माई इंडिया के सहयोग से रीयल-टाइम ट्रैफिक अलर्ट और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की चेतावनी को डिजिटल मैपिंग से जोड़ा गया है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़कों पर सशक्त पुलिसिंग ही भीड़भाड़ और अव्यवस्थित यातायात के खिलाफ सबसे मजबूत उपाय है। उन्होंने कहा कि यातायात अनुशासनहीनता, सड़क सुरक्षा में लापरवाही और सुगम आवागमन में शिथिलता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी।

गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने गलत दिशा में वाहन चलाने के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। पुलिस की ओर से उपराज्यपाल को बताया गया कि इस उल्लंघन के चालानों में पिछले वर्ष की तुलना में 113 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले साल से इस बार 1.87 लाख चालान अधिक किए गए हैं। जबकि 2321 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। अनधिकृत पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई में भी 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। संयुक्त पैदल गश्त के जरिये 399 अतिक्रमण हटाए गए और अवैध पार्किंग के 1915 मामलों में कार्रवाई की गई।

आईआईटी दिल्ली का 57वां दीक्षांत समारोह आज पीएम मोदी छात्रों को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली, 07 अगस्त (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर वह 3000 से अधिक स्नातक होने वाले विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। इनमें 587 पीएचडी शोधार्थी भी शामिल हैं, जिन्हें समारोह के दौरान उपाधियां प्रदान की जाएंगी।

शैक्षणिक उत्कृष्टता का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान के सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। इनमें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक, डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक तथा परफेक्ट टेन स्वर्ण पदक शामिल हैं। अत्याधुनिक अनुसंधान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित एआई आधारित हाई-परफॉर्मेंस सुपरकंप्यूटिंग सुविधा 'परम प्रज्ञा' का उद्घाटन भी करेंगे। अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह सुविधा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साइंस, उन्नत कंप्यूटिंग तथा बहुविषयी अनुसंधान के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने बताया कि यह सुविधा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग के क्षेत्र में देश की शोध क्षमताओं को नई गति देगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कुल 3036 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी, जिनमें 587 पीएचडी शोधार्थी, 1049 बीटेक, 567 एमटेक, 248 एमबीए और 243 एमएससी छात्र शामिल हैं। वर्ष 2026 में पहली बार बैचलर ऑफ डिजाइन, एग्जीक्यूटिव एमबीए, एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंसेज और एमए इन कल्चर, सोसाइटी एंड थॉट के पहले बैच भी स्नातक होंगे।

गुरु हरिकृष्ण साहिब का प्रकाश पर्व श्रद्धा से मनाया

कीर्तन सेवा सम्मान की घोषणा

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बाला प्रीतम गुरु हरिकृष्ण साहिब का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा बाला साहिब, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब और गुरुद्वारा सीसगंज साहिब में विशेष गुरमति समागम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

मुख्य समारोह गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में आयोजित हुआ। कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलों ने गुरु हरिकृष्ण साहिब की मानव सेवा, करुणा और समर्पण को आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया। उन्होंने कहा कि कमेटी शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा कार्यों के माध्यम से गुरु साहिब की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रही है। समारोह में डॉ. गुरनाम सिंह को 'शिरोमणि कीर्तनिए अवॉर्ड' तथा 90 वर्षीय भाई स्वर्णजीत सिंह को 'शिरोमणि कीर्तन सेवा अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। साथ ही घोषणा की गई कि दिल्ली कमेटी के अधीन उत्कृष्ट सेवा देने वाले रागी सिंहों को प्रत्येक वर्ष 1.25 लाख रुपये का विशेष सम्मान दिया जाएगा, जिसकी शुरूआत 12 सितंबर से होगी। कमेटी ने गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूलों के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा संगत से सेवा कार्यों में सहयोग की भी अपील की। समारोह में देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं और बड़ी संख्या में संगत ने भाग लेकर गुरु साहिब के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की।

चंडीगढ़ फायर विभाग का फायरमैन निकला भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड

10-12 लाख रुपये लेकर ब्लूटूथ और नैनो ईयरबड से कराते थे नकल

दिल्ली पुलिस की जनकपुरी थाना पुलिस ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हाईटेक तरीके से नकल कराने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सरगना और चंडीगढ़ फायर विभाग का फायरमैन सोनू कुमार उर्फ सोनू मान, सन्नी, दीपक, वीरेंद्र, रिंकू, हेमंत और आरती को गिरफ्तार किया है।

नई दिल्ली, वेब वार्ता

आरोपी सन्नी लेडी इरविन कॉलेज में लैब अटेंडेंट हैं वह उम्मीदवारों को गिरोह से जोड़ने का काम करता था जबकि आरोपी दीपक एजेंट के रूप में अभ्यर्थियों की व्यवस्था और तकनीकी मदद करता था। आरोपी अभ्यर्थियों से 10 से 12 लाख रुपये तक लेकर उन्हें सरकारी भर्ती परीक्षाओं में नकल कराते थे। इसके लिए कस्टमाइज्ड मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, नैनो ईयरबड और सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। आरोपियों के कब्जे से विदेशी व्हाट्सएप अकाउंट से जुड़ा टैबलेट, कस्टमाइज्ड मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, नैनो ईयरबड समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

पश्चिमी जिले के उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी के अनुसार, 26 जुलाई को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से जनकपुरी स्थित केंद्रीय विद्यालय (केवीएस) में आयोजित लोअर डिवीजन क्लर्क भर्ती परीक्षा के दौरान दो अभ्यर्थियों के अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने की शिकायत दी गई थी।

जांच के दौरान अभ्यर्थी आरती के पास से विशेष रूप से तैयार किया गया मोबाइल फोन मिला, जबकि दूसरे अभ्यर्थी हेमंत के पास से ब्लूटूथ डिवाइस, सिम कार्ड और नैनो ईयरबड बरामद हुए। शिकायत के आधार पर जनकपुरी थाने में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद पुलिस ने पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए विशेष जांच शुरू की। पूछताछ में हेमंत ने खुलासा किया कि उसके भाई रिंकू ने वीरेंद्र के माध्यम से 12 लाख रुपये में ब्लूटूथ डिवाइस और सिम कार्ड की व्यवस्था कराई थी, ताकि परीक्षा केंद्र के बाहर से उसे उत्तर बताए जा सकें। इसके आधार पर पुलिस ने रिंकू और वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर, आरती ने बताया कि उसके परिचित सन्नी ने उसे कस्टमाइज्ड मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस और नैनो ईयरबड उपलब्ध कराए थे। इसके बदले 10 लाख रुपये का सौदा तय हुआ था। जांच आगे बढ़ी तो सन्नी और उसके बाद दीपक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, सन्नी और दीपक के बीच यह सौदा आठ लाख रुपये में तय हुआ था।

विदेशी व्हाट्सऐप अकाउंट के जरिये मिलते थे प्रश्नपत्र...

तकनीकी निगरानी, सोशल मीडिया विश्लेषण और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने गिरोह के सरगना सोनू कुमार उर्फ सोनू मान की पहचान की। उसे हरियाणा के चरखी दादरी स्थित दादरी बाइपास रोड से उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह एक अन्य सरकारी भर्ती परीक्षा में नकल कराने की तैयारी कर रहा था। पुलिस का दावा है कि सोनू मान विदेशी व्हाट्सऐप अकाउंट के जरिये प्रश्नपत्र प्राप्त कर उनके उत्तर तैयार करवाता था और अपने एजेंटों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों के भीतर मौजूद अभ्यर्थियों तक पहुंचाता था। उसके पास से टैबलेट, कस्टमाइज्ड मोबाइल फोन, तीन ब्लूटूथ डिवाइस, चार नैनो ईयरबड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान, वित्तीय लेन-देन और विभिन्न राज्यों में आयोजित अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में उनकी संलिप्तता की जांच कर रही है।

आरटीआई पारदर्शिता ऑडिट में जामिया मिल्लिया इस्लामिया का शानदार प्रदर्शन

नई दिल्ली, 07 अगस्त (वेब वार्ता)। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के तहत हुए थर्ड पार्टी ट्रांसपेरेंसी ऑडिट में 825 में से 802 अंक हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। यह जामिया का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही व सुशासन के प्रति उसकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऑडिट में जामिया की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर का मूल्यांकन किया गया।

825 में से 802 अंक हासिल कर बनाया रिकॉर्ड

यह मूल्यांकन केंद्रीय सूचना आयोग से मान्यता प्राप्त सरकारी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर किया गया। जामिया ने अपनी वेबसाइट पर आरटीआई अधिनियम की धारा-4 के तहत आवश्यक सूचनाओं को व्यवस्थित व उपयोगकर्ता अनुकूल तरीके से उपलब्ध कराया है, जिससे छात्रों, अभिभावकों व आम नागरिकों को जानकारी आसानी से मिल सके। कुलपति प्रो. मजहर आसिफ ने कहा कि पारदर्शिता केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि अच्छे प्रशासन की पहचान है। रजिस्ट्रार प्रो. मो. महताब आलम रिजवी ने इसे विभिन्न विभागों के बेहतर समन्वय, नियमित निगरानी व निरंतर प्रयासों का नतीजा बताया। जामिया ने आरटीआई नोडल अधिकारी प्रो. शबाना महफूज सहित आरटीआई सेल, आईटी सेंटर व विभिन्न विभागों के अधिकारियों का आभार जताया।

जेएनयू में इस्कॉन के विरोध में छात्र संघ का प्रदर्शन

नई दिल्ली, 07 अगस्त (वेब वार्ता)। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघ ने सोमवार को सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर इस्कॉन के एक कार्यक्रम के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को लेकर छात्र संघ की ओर से पोस्टर भी जारी किया गया था। हालांकि प्रदर्शन के चलते कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका। जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष के. गोपिका बाबू ने कहा कि सेंट्रल लाइब्रेरी में इस्कॉन का कार्यक्रम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। विश्वविद्यालय को एक विचारधारा का नेतृत्व वाला केंद्र नहीं बनने देंगे। शैक्षणिक संस्थानों को छद्म विज्ञान और धार्मिक वर्चस्वाद का केंद्र नहीं बनने दिया जाना चाहिए। पिछले वर्ष नवंबर महीने में जेएनयू प्रशासन को पत्र लिखा था। इसमें बार-बार इस्कॉन संस्था को कार्यक्रम की अनुमति दिए जाने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से कोई जवाब नहीं मिल सका।

पैदल यात्रियों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत

लोनी रोड से अतिक्रमण हटाने की मांग

नई दिल्ली, 07 अगस्त (वेब वार्ता)। समाजसेवी देवेंद्र शर्मा ने पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और अतिक्रमण-मुक्त फुटपाथ सुनिश्चित करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शों का स्वागत करते हुए इसे आम नागरिकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला बताया है। उन्होंने दिल्ली की प्रमुख सड़कों, विशेषकर शाहदरा-लोनी रोड, से अतिक्रमण हटाने की मांग की।

देवेंद्र शर्मा ने कहा कि राजधानी में अनेक स्थानों पर फुटपाथों पर अवैध कब्जों के कारण पैदल चलने वाले लोगों को सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और स्कूली बच्चों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि शाहदरा-लोनी रोड पर वर्षों से अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है और समय-समय पर चलाए जाने वाले अभियान स्थायी समाधान नहीं दे पाए हैं। उनका कहना है कि कुछ दिनों बाद फिर से सार्वजनिक स्थानों पर कब्जे हो जाते हैं। देवेंद्र शर्मा ने नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली पुलिस से सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शों के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि नियमित निगरानी और सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाए तो राजधानी में पैदल यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और सम्मानजनक आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।

विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा विधायक रविन्द्र नेगी और आप विधायक कुलदीप सिंह में तीखी बहस

मिलावटी खाने एवं बदहाल स्वास्थ्य सेवा को लेकर उठे सवाल

शुक्रवार से शुरू हुए दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले ही दिन प्रश्नकाल को लेकर विधायकों में तीखी बहस हुई। खासतौर से भाजपा विधायक रविन्द्र नेगी और आप विधायक कुलदीप सिंह में काफी बहस हुई। विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य रूप से मिलावटी खाने, अस्पताल में बदहाल स्वास्थ्य सेवा, ओ-जोन के मकान और किसानों की जमीन का मुआवजा बढ़ाने को लेकर विधायकों ने सवाल पूछे।

नई दिल्ली, वेब वार्ता

आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि दिल्ली में मिलावटी सामान मिल रहा है। सभी खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट हो रही है। फल, सब्जी, दाल, मसाले आदि में मिलावट देखने को मिल रही है। दिल्ली के स्कूलों में जंक फूड दिया जा रहा है। पहले जहां एक वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति 8 लीटर तेल ग्रहण करता था तो वहीं मिलावट के चलते इसकी मात्रा 25 से 30 लीटर तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि सीबीएसई की गाइडलाइंस के तहत स्कूलों में जंक फूड पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में टास्क फोर्स होनी चाहिए जो इस तरह की मिलावट पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने आम लोगों की मदद के लिए खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय को हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने की मांग रखी ताकि लोग उस पर शिकायत कर सकें।

आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने विधानसभा में ओ-जोन में आने वाली कॉलोनियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ओ-जोन में रहने वाले लोग मकान टूटने के डर से परेशान हैं। करावल नगर में एक विधवा की 25 गज में मकान था, उसे तोड़ दिया गया। सरकार आश्वासन देती है, लेकिन कोर्ट इसे नहीं मानती। सरकार को कोर्ट में जाकर उन्हें कानूनी संरक्षण देना चाहिए। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने इस विषय पर कहा कि उपराज्यपाल से लेकर कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई है। ओ जोन के दायरे में 30 लाख लोग आते हैं। सरकार किसी का घर नहीं टूटने देगी। उन्होंने कहा लेकिन किसी का घर बन रहा तो आप के कार्यकर्ता ही शिकायत दर्ज करा रहे हैं।

राजधानी में भूमि अधिग्रहण को लेकर भी शुक्रवार को विधानसभा में आवाज उठाई गई। विधायकों की तरफ से कहा गया कि दिल्ली में पुरानी कीमतों पर जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है। हाइवे निकलते ही इसके आसपास की जमीनों की कीमत कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन अधिग्रहण करने वाले भूमि मालिकों को कम कीमत देते हैं। इतनी कीमत में रोहिणी या द्वारका में मकान योग्य भूमि भी नहीं आती है। विधायकों ने सरकार से अनुरोध किया कि वह इनकी कीमत बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाएं।

स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति

आप विधायक मोहम्मद आले इकबाल ने स्थित दिल्ली सरकार के सबसे बड़े एलएनजेपी और जीबी पंत अस्पताल में बदहाल स्वास्थ्य सेवा की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही अस्पतालों में केवल पुरानी दिल्ली के नहीं बल्कि पूरी दिल्ली से लोग उपचार के लिए आते हैं, लेकिन यहां जांच के लिए एक से दो साल बाद की तारीख दी जा रही है। अस्पताल में लोगों को वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिल रही है। वह खुद कई बार मरीजों को भर्ती कराने के लिए अस्पताल गए और आईसीयू बेड दिलाने के लिए उन्हें कई घंटे इंतजार करना पड़ा। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाए ताकि इसके अभाव में लोगों को जान न गंवाना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल में लोगों को रोकने के लिए बाउंस खड़े किए गए हैं जो मरीजों एवं परिजनों से बदसलूकी करते हैं।

सीडीओ के औचक निरीक्षण में मिलीं खामियां, पांच कर्मचारियों का वेतन रोका

लोहिया पार्क, हाईटेक नर्सरी और टीएचआर प्लांट का किया निरीक्षण

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) नेहा ब्याडवाल ने शुक्रवार को विकासखंड सुरसा के ग्राम लाल पालपुर स्थित निमार्णाधीन लोहिया पार्क, थमरावा हाईटेक नर्सरी तथा टड़ियावां स्थित टीएचआर (टेक होम राशन) प्लांट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों में देरी, उपकरण खराब मिलने, साफ-सफाई की कमी और अभिलेख उपलब्ध न कराए जाने जैसी गंभीर खामियां सामने आने पर उन्होंने पांच कर्मचारियों का वेतन रोकने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

सीडीओ ने सबसे पहले उद्यान विभाग की ओर से लगभग 1.4987 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा निर्मित कराए जा रहे लोहिया पार्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि स्वीकृत 625 मीटर बाउंड्रीवाल के सापेक्ष केवल 170 मीटर निर्माण कार्य ही पूरा हुआ है, जबकि शेष कार्य शुरू तक नहीं किया गया। इस पर उन्होंने कार्यदायी संस्था के अभियंताओं और जिला उद्यान अधिकारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

इसके बाद उन्होंने थमरावा स्थित हाईटेक नर्सरी का निरीक्षण किया। यहां सीड सोइंग मशीन और दोनों चैंबरों के चलित स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र खराब मिले। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि गत वर्ष नर्सरी का संचालन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया गया था, जबकि इस वर्ष संचालन नहीं हो रहा है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सीडीओ ने नर्सरी प्रभारी अजय कुमार वर्मा, माली अमित कुमार तथा गया प्रसाद का अगस्त 2026 का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के निर्देश दिए। साथ ही 15 दिनों के भीतर नर्सरी का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित कराने तथा अनुपालन न होने पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

इसके उपरांत सीडीओ ने टड़ियावां स्थित टीएचआर (टेक होम राशन) प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण किया। प्लांट संचालित मिला, लेकिन परिसर में साफ-सफाई संतोषजनक नहीं पाई गई। उन्होंने मौके पर तैयार किए जा रहे पोषाहार की गुणवत्ता की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूने लेने के निर्देश दिए। इसके अनुपालन में सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुराग सिंह ने पोषाहार के नमूने एकत्र किए।

आवश्यक कार्रवाई करने के दिये निर्देश

निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने जून 2026 में प्राप्त सामग्री का स्टॉक रजिस्टर और अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन नोडल बीएमएम अभिलेख उपलब्ध नहीं करा सके। इस पर उन्होंने अभिलेखों का मिलान होने तक नोडल बीएमएम आशीष कुमार मिश्र एवं सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) नितिन कुमार का वेतन रोकने तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश उपायुक्त, स्वतः रोजगार को दिए।

इनकी रही उपस्थिति

निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के सहायक अभियंता इं. अजय पाल सिंह, अवर अभियंता आशीष कुमार, जिला उद्यान अधिकारी डॉ. सुभाष चंद्र, खंड विकास अधिकारी हरियावां सत्यदेव यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

विधानसभा में गूंजा किसानों के पट्टे का मुद्दा, संक्रमणीय भूमि बनने की जगी उम्मीद

वेबवार्ता/हरदोई

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में सभापति अशोक अग्रवाल ने गरीब किसानों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने नियम-115 के अंतर्गत उन किसानों की समस्या सदन के सामने रखी, जिन्हें वर्षों पहले कृषि पट्टे तो आवंटित कर दिए गए, लेकिन आज तक उनकी भूमि संक्रमणीय नहीं हो सकी। इससे किसानों को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए लगातार तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार गरीब एवं भूमिहीन किसानों को कृषि पट्टा आवंटित कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की व्यवस्था है। इसके लिए भूमि प्रबंधन समिति के प्रस्ताव एवं खुली बैठकों के माध्यम से पात्र किसानों का चयन कर प्रस्ताव उपजिलाधिकारी को भेजा जाता है। स्वीकृति मिलने के बाद किसानों को कृषि भूमि का पट्टा आवंटित कर दिया जाता है।

हालांकि, किसानों का कहना है कि नियमानुसार पांच वर्ष पूर्ण होने के बाद पट्टे की भूमि को संक्रमणीय किया जाना चाहिए, लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद बड़ी संख्या में किसानों की भूमि आज भी असंक्रमणीय बनी हुई है। इसके चलते वे अपनी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व संबंधी अधिकारों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और उन्हें समय व आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है।

सभापति अशोक अग्रवाल ने सदन में इस ज्वलंत समस्या को उठाते हुए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन करते हुए पात्र किसानों की भूमि को समयबद्ध तरीके से संक्रमणीय बनाया जाना चाहिए, ताकि उन्हें अपने अधिकारों के लिए भटकना न पड़े।

जगी है नई उम्मीद

सदन में यह मुद्दा उठने के बाद क्षेत्र के सैकड़ों किसानों में नई उम्मीद जगी है कि लंबे समय से लंबित उनकी पट्टे की भूमि जल्द ही संक्रमणीय घोषित होगी। यदि ऐसा होता है तो किसानों को तहसीलों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और वे अपनी भूमि पर नियमानुसार पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकेंगे।

छत के रास्ते घर में घुसे चोर

किसान की अलमारी साफ कर ले गए नकदी और जेवर

वेबवार्ता/हरदोई

कोतवाली कछौना क्षेत्र के ग्राम सुठेना में गुरुवार देर रात अज्ञात चोरों ने एक किसान के घर को निशाना बनाते हुए छत के रास्ते घर में प्रवेश कर लाखों रुपये की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर में रखी एक लाख रुपये की नकदी के साथ सोने-चांदी के कीमती जेवरात समेट ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।

ग्राम सुठेना निवासी किसान श्याम गुरुवार रात परिवार के साथ भोजन करने के बाद घर में सो रहे थे। इसी दौरान देर रात अज्ञात चोर छत के रास्ते घर में घुस गए। चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखी एक लाख रुपये की नकदी, सोने का मंगलसूत्र, एक जोड़ी सोने की झुमकी, दो जोड़ी बिछिया, दो जोड़ी पायल सहित अन्य कीमती जेवरात चोरी कर लिए। चोरी गए सामान की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है।

शुक्रवार सुबह किसान की पत्नी की नींद खुली तो घर के दरवाजे खुले मिले। कमरे का ताला टूटा हुआ था और अलमारी का सामान बिखरा पड़ा था। यह देखकर परिवार के होश उड़ गए। पीड़ित किसान ने तत्काल घटना की सूचना कोतवाली कछौना पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके। मामले में पीड़ित की तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। कछौना पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरी का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कसा शिकंजा

वेब वार्ता, हरी शंकर शर्मा

कानपुर। राज्य में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपना लिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन के सख्त निदेशों और अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) डी. के. सिंह के मार्गदर्शन में कानपुर नगर में एक विशेष सघन अभियान 'मिशन आरोही' चलाया गया। इस अभियान के तहत कानपुर मंडल आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव की अगुवाई में प्रवर्तन टीम और एडीसीपी ट्रैफिक व पुलिस की संयुक्त टीम ने गंगा बैराज चौराहे पर उतरकर कर बड़े पैमाने पर मिशन आरोहीअभियान चलाया। 'मिशन आरोही के दौरान 360 वाहनों का विभिन्न अभियोग में चालान किया गया तो वही 26 वाहनों पर सीज की कार्यवाही की गई। इनमें मुख्य रूप से बिना हेलमेट व सीटबेल्ट लगाए वाहन चलाने वाले, ओवरस्पीडिंग और ओवरलोडिंग करने वाले व्यावसायिक वाहन, बिना वैध परमिट, फिटनेस व प्रदूषण प्रमाण पत्र के संचालित हो रहे वाहनों तथा निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर शिकंजा कसा गया। कानपुर मंडल आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि 'मिशन आरोही' का मुख्य उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सड़कों पर अनुशासित यातायात व्यवस्था कायम करना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और इस प्रकार का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

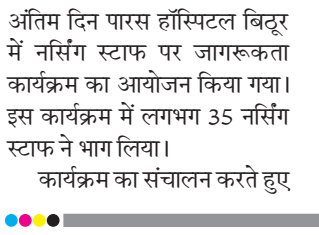

भारी विरोध और हंगामे के बीच अवैध डेयरियों पर नगर निगम का प्रहार, 34 पशु जब्त

वेब वार्ता, लखनऊ

नियम से गाय पालने वालों को नहीं होगी परेशानी: डॉ. अभिनव वर्मा

पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने स्पष्ट किया कि नगर निगम की कार्रवाई का उद्देश्य नियमों का पालन करते हुए गाय अथवा अन्य पशु पालने वाले लोगों को परेशान करना नहीं है। नियमों के अनुरूप पशुपालन करने वालों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। कार्रवाई केवल अवैध डेरी संचालन, सार्वजनिक मार्गों पर पशुओं को बांधने और अतिक्रमण कर व्यावसायिक रूप से पशुपालन करने वालों के विरुद्ध की जा रही है।

नगर निगम लखनऊ ने अवैध डेयरियों और सार्वजनिक मार्गों पर पशु बांधकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार, 07 अगस्त 2026 को जोन-4 के विभिन्न क्षेत्रों में भारी विरोध और हंगामे के बीच विशेष अभियान चलाकर अवैध डेयरियों पर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुल 34 पशुओं को पकड़कर आलमबाग कांजी हाउस में निरुद्ध कराया गया।

पशु कल्याण अधिकारी के निर्देश पर चला संयुक्त अभियान

पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के निर्देश पर नगर निगम के प्रवर्तन दल और कैटिल कैचिंग दस्ते ने संयुक्त रूप से जोन-4 क्षेत्र में अभियान चलाया। इस दौरान निशातगंज, वास्तु खंड, ग्वारी और तखवा गांव में संचालित अवैध दूध डेयरियों के साथ ही सार्वजनिक सड़कों और मार्गों पर बांधे गए पशुओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

निशातगंज में टीम को देख पशुओं को बंद कर लगाया ताला

निशातगंज की छठी लेन में नगर निगम की टीम पहुंचते ही डेरी संचालकों ने कार्रवाई से बचने के लिए पशुओं को एक स्थान पर बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। नगर निगम की टीम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ताला खुलवाने का प्रयास किया। सहयोग न मिलने पर ताला तोड़कर अंदर बंद पशुओं को बाहर निकाला गया और उन्हें जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय स्तर पर विरोध और हंगामा भी हुआ, लेकिन नगर निगम की टीम ने अभियान जारी रखा। तखवा गांव में भी सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण कर पशुपालन और डेरी संचालन किए जाने का मामला सामने आया। पशुओं को सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर बांधे जाने से आवागमन प्रभावित हो रहा था। नगर निगम की टीम ने मौके पर अवैध रूप से किए गए पशुपालन को बंद कराया और संबंधित पशुओं को जब्त कर सार्वजनिक मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त कराया।

24 गाय और सात भैंस समेत कुल 34 पशु पकड़े गए

विशेष अभियान के दौरान नगर निगम की टीम ने 24 गाय, दो बछिया, एक बछड़ा और सात भैंस समेत कुल 34 पशुओं को पकड़ा। सभी जब्त पशुओं को नगर निगम के आलमबाग कांजी हाउस में निरुद्ध कराया गया। अभियान के दौरान प्रवर्तन दल और कैटिल कैचिंग दस्ते ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बाद अब सुकन्या समृद्धि अभियान पर डीएम सत्य प्रकाश का फोकस

ललितपुर,(आलोक चतुर्वेदी। निराश्रित बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जोड़कर आर्थिक संबल प्रदान करने के बाद अब जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने जनपद की बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को जन-जन तक पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया है। उनका उद्देश्य है कि जनपद की कोई भी पात्र बालिका जानकारी या संसाधनों के अभाव में इस महत्वपूर्ण सरकारी योजना से वंचित न रहे।

मां के दूध में विटामिन, वसा और प्रोटीन होते हैं - डॉ शैलेंद्र गौतम

वेब वार्ता, कानपुर

भारतीय बाल रोग अकादमी द्वारा विश्व स्तन पान सप्ताह के अंतिम दिन पारस हॉस्पिटल बिठूर में नर्सिंग स्टाफ पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 35 नर्सिंग स्टाफ ने भाग लिया।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉ शीला चित्रांशी ने बताया कि स्तनपान का अर्थ है , कि शिशु को सीधे स्तन से दूध पिलाना । नवजात शिशु हर 2 से 3 घंटे में दूध पीते है जैसे - जैसे शिशु बढ़ता है स्तनपान की आवृत्ति बदलती रहती हैं। मां के दूध में विटामिन, वसा और प्रोटीन होते हैं और यह शिशु को संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। इसी क्रम

डॉ प्रीति शुक्ला ने बताया स्तनपान कराने वाली माताओं का गर्भाशय जल्दी अपने सामान्य आकार में आ जाता है, स्तन कैंसर व अन्य बामारियों का होने खतरा कम होता हैं। इस अवसर पर बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ शैलेन्द्र गौतम ने स्तनपान से संबंधित विभिन्न जानकारी दी और सभी माताओं से अपील की , कि वह पाने शिशुओ को स्तनपान करवाए न कि ऊपर का।

संक्षिप्त वार्ता

ब्लॉक संसाधन केंद्र कछौना में आधार कार्य ठप

वेबवार्ता/हरदोई। ब्लॉक संसाधन केंद्र कछौना में पिछले एक वर्ष से आधार कार्ड नामांकन केंद्र का कार्य प्रभावित होने से क्षेत्रीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नया आधार कार्ड बनवाने, नाम एवं पता संशोधन, बायोमेट्रिक अपडेट तथा मोबाइल नंबर लिंक कराने जैसे आवश्यक कार्य ठप होने से लोग दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

जनसरोकार मंच ने इस गंभीर समस्या को विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) एवं सभापति अशोक अग्रवाल के संज्ञान में लाया। शिकायत मिलने के बाद उन्होंने जिलाधिकारी हरदोई को पत्र लिखकर आधार नामांकन केंद्र को शीघ्र सुचारू रूप से संचालित कराने की मांग की है। वर्तमान समय में आधार कार्ड की उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है। विद्यालयों में प्रवेश, छात्रवृत्ति, पेंशन, राशन, बैंकिंग सेवाओं सहित लगभग सभी सरकारी योजनाओं में आधार अनिवार्य हो चुका है। ऐसे में कछौना और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग सुबह से ही विभिन्न केंद्रों के चक्कर लगाने को विवश हैं, लेकिन उन्हें आवश्यक सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। बताया गया कि ब्लॉक संसाधन केंद्र कछौना में आधार संबंधी सेवाएं एक वर्ष से प्रभावित हैं, जिससे लगभग दो लाख की आबादी प्रभावित हो रही है। सबसे अधिक परेशानी छोटे बच्चों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को उठानी पड़ रही है। आधार संबंधी कार्य समय पर न होने से विद्यालयों में नामांकन सहित कई जरूरी प्रक्रियाएं बाधित हो रही हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों तक समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में सरकार का "मेरा आधार, मेरी पहचान" का स्लोगन लोगों के लिए केवल एक नारा बनकर रह गया है।

2017 से फरार दो शातिर अभियुक्तों को जीआरपी ने किया गिरफ्तार

वेब वार्ता, कानपुर। पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी० द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में ट्रेनों में हो रही चोरी की घटनाओं की रोकथाम, अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान में प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल ओम नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में जीआरपी पुलिस ने मुकदमे में एनबीडब्ल्यू वांछित चल रहे दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।

पकड़े गए अभियुक्तों में संदीप सिंह (34) पुत्र राजेन्द्र सिंह नि0 ग्राम अकबरपुर डाढ़ा थाना फंफूद जिला औरैया व अभि० मो0 आमिर पुत्र महबूब आलम नि0 1/113 ईदगाह सफेद कालोनी थाना बाबूपुरवा है। इन पर एनबीडब्लू समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

जीआरपी प्रभारी निरीक्षक ओम नारायण सिंह ने बताया कि ये दोनों अभियुक्त वर्ष 2017 से फरार चल रहे थे तथा मा. एडीजे- 22 कानपुर नगर द्वारा दोनों अभियुक्तों पर गैर जमानती वारंट भी किया था। पुलिस ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी के लिए गठित टीम द्वारा इलेक्ट्रानिक तथा खास मुखबिर की सूचना के आधार पर काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा था। पकड़ने वाली टीम में प्रमुख रूप से एसआई विनोद कुमार यादव, शिवबाबू यादव,अर्पित तिवारी थाना जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल, हे0 कां० नृपेन्द्र कुमार, अनुराग कुमार चौकी जीआरपी झींझक थाना जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल, शिव सिंह, रमेश सोनकर, वैश खान, सत्येन्द्र सिंह, राजकमल वर्मा रहे।

विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता प्रशिक्षण समारोह का हुआ आयोजन

वेब वार्ता, कानपुर। विश्व स्तनपान सप्ताह के समापनअवसर पर प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज, कानपुर द्वारा ह्यस्तनपान जागरूकता प्रशिक्षण मॉड्यूलह्व के अंतर्गत आयोजित सप्ताहव्यापी प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम समारोह का शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. सीमा द्विवेदी के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में किया गया।

स्तनपान सप्ताह के समापन अवसर पर इस प्रशिक्षण का उद्देश्य चिकित्सकों, रेजिडेंट चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों को स्तनपान संबंधी नवीनतम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिशानिदेर्शों से अवगत कराना तथा माताओं में जन्म के प्रथम घंटे में स्तनपान प्रारंभ करने, छह माह तक केवल माँ का दूध पिलाने तथा दो वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखने के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. मीरा अग्निहोत्री, प्रतिष्ठित कनिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में प्रतिभाग किया किया। विशिष्ट अतिथियों में डॉ. किरण पांडेय (उत्तर प्रदेश प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ संघ की अध्यक्ष), डॉ. नीलम मिश्रा (इंडियन सोसायटी ऑफ पेरिनेटोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, कानपुर शाखा की अध्यक्ष), डॉ. कल्पना (कानपुर प्रसूति एवं स्त्री रोग सोसायटी की पूर्व अध्यक्ष) तथा डॉ. रेनू टंडन (कानपुर प्रसूति एवं स्त्री रोग सोसायटी की सचिव) उपस्थित रहीं।

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पूर्व मंत्री स्व.हनुमंत सिंह को दी श्रद्धांजलि

वेब वार्ता, कमर खान

बलरामपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता स्वतंत्र देव सिंह ने शुक्रवार को बलरामपुर पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हनुमंत सिंह के शारदा कुंज स्थित आवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्वर्गीय हनुमंत सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्वर्गीय हनुमंत सिंह के भाई शिव प्रताप सिंह एवं पुत्र अखिलेश सिंह (गुड्डू) से भेंट कर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की तथा शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाते हुए इस कठिन घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय हनुमंत सिंह का सार्वजनिक जीवन और समाज के प्रति उनकी सेवाएं सदैव स्मरणीय रहेंगी। उनके निधन से क्षेत्र और समाज को अपूरणीय क्षति हुई है।

सहरिया समाज के लिए बदली तस्वीर, अब दस्तावेजों के अभाव में नहीं छिनेगा योजनाओं का हक

वेब वार्ता, ललितपुर/आलोक चतुर्वेदी। वर्षों से सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए जरूरी दस्तावेजों के अभाव में विकास की मुख्यधारा से दूर रहे सहरिया आदिवासी समुदाय के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी पहल शुरू की है। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की पहल पर जिले में सहरिया संतृप्तिकरण अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत सहरिया बाहुल्य गांवों में शिविर लगाकर आधार कार्ड, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जॉब कार्ड समेत विभिन्न जरूरी दस्तावेज मौके पर ही तैयार कराए जा रहे हैं। दस्तावेज बनने के बाद पात्र परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है।

महत्वपूर्ण ख़बर

मुर्गियों के पंखों का रंग एमसी1आर नामक जीन से होता है नियंत्रित

- टेक्सस। मुर्गियों के पंखों का रंग मुख्य रूप से एमसी1आर नामक जीन से नियंत्रित होता है। इसी जीन में समय के साथ होने वाले बदलावों के कारण आज विभिन्न रंगों की मुर्गियां देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि एक ही प्रजाति से संबंध रखने के बावजूद मुर्गियों के पंखों के रंगों में इतना अंतर होता है। टेक्सस ए एंड एम कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में पाए जाने वाले जंगली रेड जंगलफाउल से लेकर आधुनिक घरेलू मुर्गियों तक के विकासक्रम को समझने में यह अध्ययन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही, इससे पोल्ट्री उद्योग और प्रजनन कार्यक्रमों में भी नई जानकारी मिलने की उम्मीद है।

आरक्षण को लेकर फिर तेज हुई बहस और विरोध की आवाजें

कई संगठनों ने उठाए सवाल, ऑनलाइन माध्यमों पर बड़ी संख्या में समर्थकों को आकर्षित करने का किया जा रहा दावा

नई दिल्ली। देश में जाति-आधारित आरक्षण को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज होती नजर आ रही है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया अभियानों, कई संगठनों के प्रदर्शनों और सार्वजनिक बयानों के चलते आरक्षण व्यवस्था पर चर्चा नए सिरे से केंद्र में आ गई है। इस बीच कुछ संगठनों ने आरक्षण नीति में बदलाव की मांग उठाई है, जबकि अन्य पक्ष मौजूदा व्यवस्था को सामाजिक न्याय के लिए जरुरी बता रहे हैं। हाल के सप्ताहों में सोशल मीडिया पर आरक्षण संबंधी कई अभियान तेजी से चर्चा में आए हैं। इन्हीं में एक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नामक अभियान भी शामिल है, जिसने ऑनलाइन माध्यमों पर बड़ी संख्या में समर्थकों को आकर्षित करने का दावा किया है। इस अभियान से जुड़े लोग जाति-आधारित आरक्षण की समीक्षा और मेरिट आधारित व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं। अभियान के समर्थकों ने हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में विरोध प्रदर्शन भी किया।

इसी क्रम में नीट परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर हुई बहस में आरक्षण के मुद्दे पर मुखर हुए कुछ युवाओं ने भी सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता बढ़ाई है। इनमें हर्ष दुबे का नाम भी चर्चा में है, जिन्होंने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति के लिए आवेदन किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भी आरक्षण और यूजीसी के जाति समानता संबंधी प्रस्तावित नियमों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पुलिस के साथ झड़प की घटनाएं सामने आईं। संगठन के नेताओं ने स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को समर्थन नहीं देने की घोषणा की। आरक्षण पर चल रही इस बहस में शिक्षाविदों, लेखकों, पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बीच भी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। एक वर्ग वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को सामाजिक समानता के लिए जरुरी मानता है, जबकि दूसरा वर्ग इसकी समीक्षा या समाप्ति की मांग कर रहा है।

चर्चा आगे भी जारी रहने की संभावना है

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक स्तर पर अधिकांश दल इस संवेदनशील मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस बहस के राजनीतिक प्रभावों पर भी नजर रखी जा रही है। 2027 में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना हैं, जिसके बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हैं। विशेष रूप से यूपी में जातीय समीकरण लंबे समय से चुनावी राजनीति का प्रमुख आधार रहे हैं। पिछले चुनावों में कांग्रेस के जितनी आबादी, उतना हक और समाजवादी पार्टी के पीडीए जैसे नारों ने राजनीतिक विमर्श को प्रभावित किया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरक्षण को लेकर चल रही नई बहस भी आने वाले चुनावों में कई दलों की रणनीति और सामाजिक समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। आरक्षण का विषय लंबे समय से भारतीय राजनीति और समाज का संवेदनशील मुद्दा रहा है। ऐसे में इस पर उभरती बहस के बीच कई पक्षों के तर्क और संवैधानिक प्रावधानों को लेकर चर्चा आगे भी जारी रहने की संभावना है।

यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी से सूख रहीं नदियां

मैड्रिड। यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब नदियों पर भी दिखने लगा है। सर्बिया के प्राहोवो इलाके के पास डानुबे नदी का पानी कम हो गया है। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के समय डुबोए गए नाजी जर्मनी के कई युद्धपोत दिखाई देने लगे हैं। यह ऐसे समय में हुआ है, जब यूरोप के कई देश तेज गर्मी, सूखे और जंगल की आग से जूझ रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ती गर्मी और कम बारिश की वजह से नदियों का पानी घट रहा है। क्लाइट चेंज भी इसकी बड़ी वजह है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पानी कम होने के बाद इन युद्धपोतों के कई हिस्से अब साफ दिखाई दे रहे हैं। इनमें जहाज का कंट्रोल वाला हिस्सा, तोपें और जंग लगे लोहे के ढांचे शामिल हैं। इतिहासकार इसे दूसरे विश्व युद्ध की अहम निशानी मान रहे हैं। वहीं, वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलते मौसम का बड़ा संकेत है। साल 1944 में जब नाजी जर्मनी की सेना पीछे

हट रही थी, तब उसने अपने कई युद्धपोत खुद ही डानुबे नदी में डुबो दिए थे। ऐसा इसलिए किया था ताकि सोवियत सेना इन जहाजों पर कब्जा न कर सके। अब करीब 80 साल बाद नदी का पानी घटने से ये जहाज फिर दिखाई देने लगे हैं।

डानुबे यूरोप की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह करीब 2850 किलोमीटर लंबी है और 10 देशों से होकर गुजरती है। पिछले कुछ हफ्तों से यहां तेज गर्मी और कम बारिश हो रही है। इसी वजह से नदी का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हाल ही में पानी का स्तर सिर्फ 23 सेंटीमीटर रह गया, जो 2018 के रिकॉर्ड से भी कम है। जानकारों का कहना है कि इन पुराने जहाजों में आज भी बिना फटे गोला-बारूद हो सकते हैं। इसलिए पानी और कम होने पर नदी में चलने वाले जहाजों के लिए खतरा बढ़ सकता है। कम पानी की वजह से माल ढुलाई, नावों की आवाजाही और नदी पर्यटन पर भी असर पड़ा है। कुछ बिजली संयंत्रों को भी पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

डानुबे नदी से बाहर आए ये युद्धपोत सिर्फ 80 साल पुराने इतिहास की कहानी नहीं बताते। ये यह भी दिखाते हैं कि बढ़ती गर्मी और क्लाइमेट चेंज अब दुनिया को किस तरह बदल रहे हैं। अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा, तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और ज्यादा देखने को मिल सकती हैं।

ट्रैफिक चालान बकाया मामले में यूपी सबसे आगे

दिल्ली में 2021 से 11,150 करोड़ रुपये के ट्रैफिक चालान हैं बकाया

नई दिल्ली। देशभर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जारी ई-चालानों की बकाया राशि लगातार बढ़ती ही जा रही है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2021 से 30 जुलाई 2026 तक जारी ई-चालानों में सबसे अधिक बकाया राशि उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, जबकि दिल्ली दूसरे स्थान पर है। सरकार ने बढ़ते बकाया पर चिंता जताते हुए बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

राज्यसभा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दिए गए लिखित उत्तर के अनुसार, उत्तर प्रदेश में इस अवधि के दौरान करीब 11,331 करोड़ रुपये के ट्रैफिक चालान बकाया हैं। इसके बाद दिल्ली में लगभग 11,150 करोड़ रुपये की बकाया राशि दर्ज की गई है। दोनों राज्यों की हिस्सेदारी देशभर के कुल बकाया चालानों का 50 प्रतिशत से अधिक है। तमिलनाडु 3,601 करोड़ रुपये के लंबित चालानों के साथ तीसरे स्थान पर है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगाए गए करीब 43,000 करोड़ रुपये के जुमार्ने का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। यह स्थिति ट्रैफिक नियमों के प्रभावी अनुपालन और जुमार्ना वसूली की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। ई-चालानों की संख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहां जनवरी 2021 से अब तक 7 करोड़ 89 लाख से अधिक ई-चालान जारी किए गए। तमिलनाडु 6 करोड़ 37 लाख चालानों के साथ दूसरे, जबकि दिल्ली 4 करोड़ 71 लाख चालानों के साथ तीसरे स्थान पर है। केरल में इसी अवधि में 4 करोड़ 58 लाख ई-चालान जारी किए गए।

रद्द किया जा सकता है लाइसेंस

सांसद संजय सेठ के प्रश्न के उत्तर में नितिन गडकरी ने बताया कि बकाया जुमार्ने की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (थर्ड अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 लागू किए हैं। नए प्रावधानों के तहत जनवरी 2026 से शुरू होने वाले एक वर्ष की अवधि में यदि कोई चालक पांच या उससे अधिक बार गंभीर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा।

उत्तराखंड चुनाव: हारी सीटों और जेन-जी पर रहेगा भाजपा का फोकस

नई दिल्ली। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। नई दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में संगठन को मजबूत करने, पिछली बार हारी 23 विधानसभा सीटों पर विशेष अभियान चलाने और युवाओं, खासकर जेन-जी मतदाताओं तक प्रभावी पहुंच बनाने की रणनीति तय की गई। पार्टी का लक्ष्य लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी.एल. संतोष तथा राज्य के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में चुनावी तैयारियों, संगठन की सक्रियता, सरकार और संगठन के बेहतर

समन्वय तथा जमीनी स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथ से निकली 23 सीटों पर विशेष फोकस करने का निर्णय लिया गया। इन सीटों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री, सांसदों, मंत्रियों और वरिष्ठ संगठन पदाधिकारियों को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा, सांसद अनिल बलूनी को बदरीनाथ और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पिरान कलियर सीट की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह प्रत्येक हारी हुई सीट के लिए अलग-अलग नेताओं को जवाबदेही सौंपी गई है, ताकि चुनाव से पहले वहां संगठन को मजबूत किया जा सके।

भाजपा नेतृत्व ने युवाओं, विशेषकर जेन-जी मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने पर विशेष जोर दिया है। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र स्तर पर अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पुराने कार्यकर्ताओं को भी दोबारा सक्रिय भूमिका में लाने की योजना बनाई गई है, ताकि बूथ स्तर तक संगठन की पकड़ मजबूत हो सके। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना चुनावी सफलता के लिए आवश्यक होगा। केंद्रीय नेतृत्व ने नेताओं को आपसी खेमेबाजी से बचने और सभी को साथ लेकर काम करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा गया कि सत्ता विरोधी माहौल की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जनता की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता से किया जाए और लोगों से लगातार संवाद बनाए रखा जाए।

चुनावी रणनीति के प्रमुख आधार होंगे

चुनाव में अब छह महीने से भी कम समय शेष रहने के कारण पार्टी ने बूथ स्तर पर अभियान तेज करने का निर्णय लिया है। नेताओं के अधिकाधिक प्रवास, लाभार्थी सम्मेलन, जनसंपर्क अभियान और सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों को आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य इकाई से पूर्व में दिए गए निदेशों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की और आगामी महीनों में संगठनात्मक गतिविधियों को और गति देने के निर्देश दिए। भाजपा का मानना है कि मजबूत संगठन, प्रभावी जनसंपर्क और युवा मतदाताओं तक पहुंच उसकी चुनावी रणनीति के प्रमुख आधार होंगे।

इटली में घटती जन्मदर बनी चिंता का कारण

रोम। इटली इन दिनों एक बड़े सामाजिक और जनसांख्यिकीय बदलाव के कारण चर्चा में है। यहां पालतू जानवरों की संख्या बच्चों से कई गुना अधिक हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो यह केवल जीवनशैली में बदलाव का संकेत नहीं, बल्कि घटती जन्मदर और बदलती पारिवारिक प्राथमिकताओं का भी स्पष्ट प्रमाण है।

यही कारण है कि यह स्थिति सरकार, समाजशास्त्रियों और जनसंख्या विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। इटली के पालतू पशु उद्योग संगठन अस्साल्को के अनुमान के अनुसार, देश में लगभग 5.36 करोड़ पालतू जानवर हैं। इनमें करीब 2.5 करोड़ मछलियां, लगभग 1.1 करोड़ बिल्लियां और 91 लाख कुत्ते शामिल हैं। इसके अलावा पक्षियों, खरगोशों और अन्य छोटे पालतू जीवों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसके विपरीत, देश में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या केवल लगभग 76 लाख रह गई है। यह अंतर दशार्ता है कि इटली में पारिवारिक ढांचे और सामाजिक प्राथमिकताओं में तेजी से बदलाव आ रहा है। आंकड़ों के अनुसार, इटली में हर वर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या घटकर लगभग 3.93 लाख रह गई है, जो हाल के वर्षों का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है।

देश की कुल प्रजनन दर भी घटकर प्रति महिला लगभग 1.18 बच्चे रह गई है, जबकि किसी भी देश की जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए यह दर करीब 2.1 होनी चाहिए। इतनी कम जन्मदर भविष्य में आबादी घटने और बुजुर्गों की संख्या बढ़ने जैसी चुनौतियों का संकेत देती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक अनिश्चितता, महंगे मकान, बढ़ती महंगाई और रोजगार की अस्थिरता के कारण बड़ी संख्या में युवा विवाह और माता-पिता बनने का निर्णय टाल रहे हैं। इसके साथ ही आधुनिक जीवनशैली, करियर पर बढ़ता ध्यान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और यात्रा जैसी प्राथमिकताएं भी परिवार बढ़ाने के फैसले को प्रभावित कर रही हैं। इसी बीच, इटली में पालतू जानवरों को परिवार का हिस्सा मानने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार, करीब 54.5 प्रतिशत परिवारों के पास कम से कम एक पालतू जानवर है।

कनाडा में भारतीय युवाओं को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

स्टूडेंट वीजा से गैंग नेटवर्क तक पर है नजर

टोरंटो। कनाडा में पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के बीच एक रिपोर्ट ने इमिग्रेशन व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ संगठित आपराधिक नेटवर्क कथित तौर पर स्टडी और वर्क परमिट के रास्ते लोगों को कनाडा पहुंचाकर अपनी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (सीबीएसए) की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए भारत में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क पर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि कुछ भारतीय नागरिक, जो पढ़ाई या काम के लिए कनाडा पहुंचे थे, कथित तौर पर जबरन वसूली, हिंसा और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े पाए गए हैं।

इस मामले में गोल्डी बराड़ का नाम प्रमुखता से सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, बिश्नोई का करीबी माने जाने वाला बराड़ 2017 में स्टूडेंट वीजा के जरिए कनाडा पहुंचा था। उसने ब्रिटिश कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया था। बाद में उस पर कनाडा में बिश्नोई नेटवर्क को मजबूत करने के आरोप लगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, जांच एजेंसियों की चिंता यह है कि कुछ युवाओं को पहले वैध इमिग्रेशन माध्यमों से कनाडा भेजा गया और बाद में कथित तौर पर अपराधी नेटवर्क में शामिल किया गया। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय छात्रों का बड़ा समुदाय अपराध से जुड़ा है। ऐसे मामलों में आरोपी लोगों की संख्या कुल भारतीय छात्रों की तुलना में बहुत कम बताई गई है। रिपोर्ट में 2016 से 2024 के बीच भारतीय स्टडी परमिट धारकों से जुड़े आपराधिक मामलों में तेज बढ़ोतरी का दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि कुछ वर्षों के दौरान हजारों आरोप दर्ज किए गए, जिनमें कुछ गंभीर अपराधों से संबंधित थे। हालांकि इन आंकड़ों और दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

कनाडाई एजेंसियां अब यह जांच कर रही हैं कि संदिग्ध लोगों को देश में प्रवेश दिलाने में किस तरह की मदद मिली, दस्तावेजों की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई और वहां पहुंचने के बाद वे किन नेटवर्क से जुड़े। इस मामले ने कनाडा की अस्थायी इमिग्रेशन व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि स्टडी और वर्क परमिट जैसे रास्तों का गलत इस्तेमाल रोकना बड़ी चुनौती है। इसी कारण कनाडा ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या नियंत्रित करने के लिए नियमों में बदलाव भी किए हैं। भारत और कनाडा के संबंधों में पहले से ही सुरक्षा और संगठित अपराध को लेकर मतभेद रहे हैं।

हवा में ही चार्ज होंगे ड्रोन, बदलेगी निगरानी और डिलीवरी की दुनिया

बीजिंग। ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसी प्रणाली विकसित की है, जिसमें उड़ते हुए ड्रोन को जमीन पर उतारे बिना ही लेजर बीम के जरिए ऊर्जा दी जा सकती है। इस तकनीक के सफल होने पर ड्रोन लंबे समय तक लगातार उड़ान भर सकेंगे और बार-बार बैटरी चार्ज करने की जरूरत कम हो जाएगी। इस नई प्रणाली को चीन की सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी और सिंगहुआ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। वैज्ञानिकों ने एक छोटे ड्रोन के नीचे विशेष रिसीवर लगाया, जो सौर पैनल की तरह काम करता है। इस

रिसीवर पर हरे रंग की उच्च-शक्ति वाली लेजर किरण डाली गई, जिसे उसने प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। इस ऊर्जा से ड्रोन के प्रोपेलर को चलाने में सफलता मिली।

शोधकर्ताओं के अनुसार, यह सिस्टम लेजर से मिलने वाली ऊर्जा का करीब 38.5 प्रतिशत हिस्सा बिजली में बदलने में सक्षम रहा है। इसे लेजर आधारित वायरलेस पावर ट्रांसफर तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। हालांकि, शुरूआती परीक्षणों में वैज्ञानिकों के सामने कई चुनौतियां भी आईं। तेज लेजर किरण के कारण ड्रोन का रिसीवर 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया, जिससे सिस्टम की कार्यक्षमता प्रभावित हुई। इस समस्या को दूर करने के लिए रिसीवर में विशेष सेमीकंडक्टर नैनोक्रिस्टल का इस्तेमाल किया गया, जिससे गर्मी को नियंत्रित करने में मदद मिली। इसके अलावा, ड्रोन के प्रोपेलर से पैदा होने वाली हवा ने भी कूलिंग में योगदान दिया।

अगर यह तकनीक पूरी तरह विकसित हो जाती है तो इसका इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। जंगलों की लंबे समय तक निगरानी, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव अभियान, सैन्य निगरानी और लंबी दूरी तक सामान पहुंचाने जैसे कामों में ऐसे ड्रोन बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं।

फिलहाल यह तकनीक शुरूआती चरण में है और इसे वास्तविक परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर परीक्षण की जरूरत है। सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि उड़ते हुए ड्रोन पर लेजर किरण को लगातार और बेहद सटीक तरीके से केंद्रित रखा जा सके।

हसीना का समर्थन कर फंसा क्रिकेट का हीरो शाकिब

ढाका। बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाकिब-अल-हसन कभी देश के सबसे बड़े खेल सितारों में गिने जाते थे, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम बदलने के बाद उनकी छवि पर बड़ा असर पड़ा है। शेख हसीना के शासनकाल के दौरान उनके साथ करीबी संबंधों और अवामी लीग से जुड़ाव को लेकर अब उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़कर देश से बाहर जाना पड़ा था। इसके बाद लंबे समय बाद उन्होंने वर्चुअल माध्यम से एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में शाकिब-अल-हसन की मौजूदगी की खबर सामने आने के बाद उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ गई। कुछ स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, उनके घर पर हमला भी किया गया।

शाकिब ने 2023 में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की सदस्यता लेकर राजनीति में कदम रखा था। 2024 के आम चुनाव में उन्होंने पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा। आलोचकों का कहना है कि उन्होंने ऐसे समय में हसीना सरकार का साथ चुना, जब देश में उनके शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। क्रिकेट के मैदान पर शाकिब का करियर बेहद शानदार रहा है। 1987 में मागुरा जिले में जन्मे शाकिब ने 2006 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। करीब दो दशक के करियर में उन्होंने बांग्लादेश के लिए सैकड़ों मैच खेले और बल्लेबाजी तथा गेंदबाजी दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें देश के सबसे सफल क्रिकेटरों में शामिल किया जाता है। हालांकि, राजनीतिक जुड़ाव के बाद उनकी लोकप्रियता प्रभावित हुई। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद कई लोग उन्हें सत्ता के करीबी चेहरे के रूप में देखने लगे।

ताजा खबर

संक्षिप्त

एशिया कप हॉकी के लिए गीता और मधु का भारतीय टीम में चयन

राजनांदगांव। चीन की धरती पर छत्तीसगढ़ी की दो बेटियां दमखम दिखाती नजर आएंगी। कबीरधाम की गीता यादव और जशपुर की मधु सिदार का चयन 30 अगस्त से 13 सितंबर 2026 तक चीन के मोकी में आयोजित जूनियर महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम में हुआ है। बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय कोचिंग कैंप में शानदार प्रदर्शन के आधार पर दोनों खिलाड़ियों को 20 सदस्यीय जूनियर इंडिया टीम में जगह मिली है। इस उपलब्धि ने न केवल प्रदेश की हॉकी प्रतिभाओं को नई पहचान दिलाई है, बल्कि यह साबित किया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने बताया कि गीता यादव पिछले तीन वर्षों से जूनियर भारतीय टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले भी वह भारतीय टीम के साथ बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी का दौरा कर चुकी हैं। चीन में आयोजित होने वाला जूनियर एशिया कप उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा बड़ा विदेशी अभियान होगा। लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर गीता ने भारतीय टीम में अपनी जगह मजबूत की है।

विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव के लिए पोषण एवं बाल कल्याण पर राज्य नीति आयोग-यूनिसेफ का मंथन

रायपुर. विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में पोषण एवं बाल कल्याण को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग में आज उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में यूनिसेफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में पोषण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण से जुड़े प्रयासों को प्रभावी बनाने तथा नवाचारों को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि पोषण और बाल कल्याण किसी भी विकसित एवं सशक्त समाज की आधारशिला हैं।

अटल डिजिटल सुविधा केंद्र बना ग्रामीणों का भरोसेमंद साथी

रायपुर. कभी बैंक का छोटा-सा काम भी गांव के लोगों के लिए पूरे दिन का सफर बन जाता था। पैसा निकालना हो, जमा करना हो या किसी सरकारी योजना की राशि प्राप्त करनी हो, इसके लिए शहर तक जाना पड़ता था। आने-जाने का खर्च अलग और मजदूरी का नुकसान अलग। लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू किए गए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ग्रामीणों के जीवन में नई सुविधा और नया विश्वास लेकर आए हैं। कबीरधाम जिले के ग्राम राजानवागांव निवासी श्रीमती गायत्री निर्मलकर के जीवन में भी अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ने बड़ा बदलाव लाया है। उनके पति श्री नोहर निर्मलकर मजदूरी और कपड़े प्रेस करने का कार्य करते हैं। परिवार की आय सीमित होने के कारण बैंक संबंधी कार्यों के लिए शहर जाना उनके लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन जाता था। कई बार बैंक जाने के कारण पूरे दिन की मजदूरी भी छूट जाती थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।

प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले शासन की योजनाओं का लाभ: मुख्यमंत्री साय

सुशासन की नई व्यवस्था- पारस पोर्टल से हर माह होगी योजनाओं की राज्यस्तरीय समीक्षा

विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित पारस पोर्टल की पहली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने सीएम हेल्पलाइन 1076, सेवा सेतु, एग्रीस्टैक, विकसित भारत जी-रामजी, डीबीएन वित्तपोषित मोबाइल टॉवर परियोजना तथा स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े प्रमुख कार्यक्रमों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को

रायपुर. शासन की योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कर आमजन को अधिकतम लाभ पहुंचाना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। डबल इंजन सरकार का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना है। इसी दृष्टि से शासन की प्रमुख योजनाओं और जनसेवाओं की नियमित निगरानी के लिए विकसित पारस (Project Assessment, Review and Analysis System) पोर्टल सुशासन का एक प्रभावी माध्यम बनेगा।मुख्यमंत्री श्री

स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप परिणाम सुनिश्चित करे। बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने राजस्व विभाग में सीमांकन से संबंधित लंबित मामलों पर विशेष नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद भी कई मामलों में समय पर सीमांकन नहीं हो रहा है। यह स्थिति आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी में डालती है तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीमांकन संबंधी प्रत्येक प्रकरण का निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि यह जमीनी स्तर पर लापरवाही तथा जिला स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव का परिणाम है। सभी कलेक्टर नियमित समीक्षा कर ऐसे मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने एग्रीस्टैक में प्रत्येक पात्र किसान का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह केवल धान खरीदी की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की आधारभूत व्यवस्था है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जिलेवार विशेष अभियान संचालित कर प्रत्येक पात्र किसान का समय पर पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष व्यवस्था के प्रारंभिक चरण में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आई थीं, लेकिन इस वर्ष किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

6,855 करोड़ रुपए से रोजगार और आधारभूत सुविधाओं का होगा विस्तार

वीबी-जी-राम-जी मिशन से ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति :सीएम

6,671 बालिका शौचालय, 6,524 मुक्तिधाम-प्रतीक्षालय, 10,027 डिफंक्ट बोरवेल में बनेंगे रिचार्ज पिट

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महानदी भवन, नवा रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में विकसित भारतङ्करोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी के अंतर्गत राज्यव्यापी मेरी बेटी मेरा अभिमान अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने घोषणा की कि 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान प्रदेश के प्रत्येक गांव में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान बेटियों के सम्मान, ग्रामीण स्वच्छता, सामाजिक गरिमा और आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार का ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय विद्यालयों में 286.85 करोड़ रुपए की लागत से 6,671 बालिका शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक शौचालय की लागत 4.30 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार प्रदेश के 6,524 गांवों में 391.44 करोड़ रुपए की लागत से प्रतीक्षालय सहित मुक्तिधाम बनाए जाएंगे, जिनकी प्रति इकाई लागत 6 लाख रुपए होगी। इसके अतिरिक्त 18.22 करोड़ रुपए की लागत से 549 मुक्तिधामों का भी निर्माण किया जाएगा, जिनकी प्रति इकाई लागत 3.32 लाख रुपए निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के 10,027 बंद अथवा डिफंक्ट बोरवेलों में 52.14 करोड़ रुपए की लागत से सैंड फिल्टर एवं रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा। प्रति इकाई लागत लगभग 52 हजार रुपए निर्धारित की गई है। इससे भू-जल स्तर में वृद्धि होगी, वर्षा जल का बेहतर संरक्षण होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल स्वीकृत कर शीघ्र प्रारंभ कराया जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू हुई है। योजना के अंतर्गत सभी विकास कार्यों का चयन ग्राम सभा की स्वीकृति से किया जाएगा तथा मजदूरी की दर बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के %विकसित भारतङ्क2047% के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगी।

उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा और वीबी-जी राम जी के माध्यम से राज्य को लगभग 6,855 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जो ग्रामीण रोजगार और विकास कार्यों के लिए राज्य में अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय निवेश है। भारत सरकार से योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1,538 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में किसानों और श्रमिकों दोनों के हितों का संतुलित ध्यान रखा गया है। कृषि कार्यों के दौरान श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष में 60 दिनों तक योजना के कार्य बंद रखने का प्रावधान किया गया है, जिससे खेती और रोजगार दोनों प्रभावित न हों।मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में 318 प्रकार के कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में शामिल किया गया है। इनमें 107 प्रकार के जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्य, 90 प्रकार के ग्रामीण अधोसंरचना विकास कार्य, 86 प्रकार के आजीविका संवर्धन कार्य तथा 35 प्रकार के जलवायु अनुकूलन एवं आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के अंतर्गत तालाब, चेकडैम, रिचार्ज संरचनाएं, सिंचाई विस्तार, भू-जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और वृक्षारोपण को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं ग्रामीण अधोसंरचना के अंतर्गत सड़क, पुलिया, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, अतिरिक्त स्कूल कक्ष, ग्रामीण पुस्तकालय, प्रयोगशाला, किचन शेड, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मुक्तिधाम और पशु चिकित्सालय जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

प्रतिबंधित एनालॉग पनीर जब्त, डेयरी का लाइसेंस निलम्बित

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की विशेष जांच अभियान में बड़ी कार्रवाई

रायपुर. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा रायगढ़ जिले में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत बुधवार को कई डेयरियों में आकस्मिक निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग नियंत्रक के निर्देश पर सतगुरु डेयरी का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान वहां से 07 किलोग्राम प्रतिबंधित एनालॉग पनीर बरामद हुआ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पनीर का नमूना जांच हेतु संग्रहित किया तथा शेष पनीर को मौके पर ही नष्ट कराया। गंभीर अनियमितता पाए जाने पर डेयरी का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर सुधार सूचना नोटिस जारी की गई।

जांच दल ने इसके बाद कस्तूरी डेयरी, सुरभि डेयरी, मुन्ना डेयरी सहित कोड़ातराई एवं पटेलपाली स्थित सतीश एवं मनोज मशरूम डेयरी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सतीश पटेल के प्रतिष्ठान से 08 किलोग्राम एक्सपायरी खोवा बरामद हुआ, जिसे ओडिशा से लाया गया था। अधिकारियों ने उक्त खोवे को मौके पर ही नष्ट कराते हुए संबंधित संचालक को नोटिस जारी किया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलेभर में इस प्रकार की विशेष जांच एवं कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। इस कार्रवाई में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेमीचंद पटेल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी शांतनु भट्टाचार्य तथा नमूना सहायक सुमन अग्रवाल उपस्थित थे।

छग की 26 सदस्यीय महिला टीम भोपाल रवाना

रायपुर. भोपाल में 8 से 10 अगस्त तक होने वाली अस्मिता नेशनल कयाकिंग एंड कैनोइंग प्रतियोगिता 2026 के लिए छत्तीसगढ़ की 26 सदस्यीय महिला टीम गुरुवार को रवाना हुई। रवाना होने से पहले खिलाड़ियों ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक आईएएस तनुजा सलाम से सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन और पदक जीतने की शुभकामनाएं दीं। छत्तीसगढ़ की महिला टीम हाल ही में रायपुर में आयोजित अस्मिता जोनल लीग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चुकी है।

ये खिलाड़ी हुए चयनित

राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ियों में तन्नू साहू, प्रिया निषाद, पलक साहू, सोनम पुजारी, मुस्कान भारती, दुतिका कश्यप, सुमनी नाग, ईशा गोयल, अंजना गोयल, मालती कश्यप, रौशनी सोढ़ी, सीमा यादव।

मनमती बघेल, पलक चौधरी, मानवी साहू, प्यारे साहू, राधा दांगी, वंशिका, गार्गी सिंह, कौशल नंदनी, स्वाति साहू, नीतू सोनवणे, कंचन नाग, कृष्णा कछारे और

कशिश निर्मलकर शामिल हैं।

19 पदक अपने नाम किए थे

इस टीम ने 8 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 पदक अपने नाम किए थे। इस प्रदर्शन के दम पर छत्तीसगढ़ की टीम प्रतियोगिता में उपविजेता रही थी।

टीम की रवानगी के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश कयाकिंग एंड कैनोइंग संघ के संयुक्त सचिव प्रशांत सिंह रघुवंशी, कोच पिंकी साहू, कोच अशोक साहू, अशोक दुबे सहित खिलाड़ी मौजूद रहे। वहीं संघ के अध्यक्ष बलदेव सिंह भाटिया, सचिव अभिजीत मिश्रा और अन्य पदाधिकारियों ने भी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।

तकनीकी खराबी के कारण उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट अस्थायी रूप से ठप

रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://highereducation.cg.gov.in/) पर सर्वर संबंधी तकनीकी समस्या के कारण उपयोगकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेबसाइट वर्तमान में अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। मिली जानकारी के अनुसार, यह समस्या वेबसाइट के स्स्रु (सिक्योर सॉकेट्स लेयर) सर्टिफिकेट से जुड़ी तकनीकी त्रुटि के कारण उत्पन्न हुई है। इस सिक्योरिटी एरर की वजह से छात्र और अन्य उपयोगकर्ता पोर्टल का सुरक्षित रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने इसका तत्काल संज्ञान लिया है और सुधार कार्य शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की तकनीकी टीम स्स्रु सर्टिफिकेट के नवीनीकरण (ऋङ्खठ्ठद्ग2ड्डद्य) और सिस्टम री-कॉन्फ़िगरेशन के काम में लगी हुई है।

सेवा सेतु पोर्टल: पारदर्शी, तेज और आसान हुई सरकारी सेवाओं की व्यवस्था

रायपुर. डिजिटल सुशासन की दिशा में राज्य शासन ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए पुराने लोक सेवा केंद्रों को आधुनिक सेवा सेतु केंद्र के रूप में विकसित किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू किए गए सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से अब प्रदेश के नागरिकों को घर बैठे 441 से अधिक शासकीय सेवाओं का लाभ मिल रहा है। यह पोर्टल शासन और जनता के बीच एक मजबूत डिजिटल सेतु के रूप में कार्य कर रहा है, जिससे सेवाएं पहले की तुलना में अधिक सरल, पारदर्शी और तेज हो गई हैं।सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को घर बैठे 441 महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध सुकमा जिला ई-गवर्नेंस विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थीं। नागरिकों की

आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए सेवा सेतु पोर्टल का विस्तार किया गया। अब इस एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्व प्रकरण तथा नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र प्रकाशन जैसी 441 महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध हैं। इससे आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बड़ी राहत मिली है और पूरी प्रक्रिया अधिक जवाबदेह एवं व्यवस्थित हो गई है। प्रत्येक सेवा के लिए निर्धारित समय-सीमा तय सेवा सेतु पोर्टल का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को मिल रहा है। अब लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति को भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। प्रत्येक सेवा के लिए निर्धारित समय-सीमा तय होने से कार्यों में तेजी आई है और पारदर्शिता बढ़ी है। इससे भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक सफल और जनहितकारी मॉडल डिजिटल तकनीक पर आधारित यह पहल न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बना रही है, बल्कि आम जनता के जीवन को भी सरल और सुविधाजनक बना रही है। सेवा सेतु पोर्टल छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक सफल और जनहितकारी मॉडल के रूप में उभर रहा है, जिससे शासन की सेवाएं अब हर नागरिक की पहुंच में और अधिक सहजता से उपलब्ध हो रही हैं।

निर्माण श्रमिकों के हित में मंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले

निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों को मंडल की बैठक में मिली स्वीकृति

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिको की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के सुधार हो रहा है। विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें की शासन की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक श्रमिकों को मिले। प्रदेश के श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बैठक को सम्बोधित करते हुए इस आशय के विचार व्यक्त किये।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की पंचम कार्यकाल की नवम बैठक आज गुरूवार को नवा रायपुर स्थित मण्डल कार्यालय में श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन श्री लखन लाल देवांगन, मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, उप सचिव श्रम विभाग श्री विपुल गुप्ता, अपर श्रमायुक्त श्री एस.एल. जांगड़े, कल्याण प्रशासक श्री सुनील मिश्रा, मण्डल के सचिव गिरीश रामटेके सहित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य

से अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नवीन सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुरूप श्रमिक कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य के 20 चयनित विद्यालयों में 200 निर्माण श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 6वीं में नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सहायता राशि का एकरूपीकरण करने का निर्णय भी लिया गया, जिससे अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिल सके। इसी प्रकार अटल करियर निर्माण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1,000 निर्माण श्रमिकों के बच्चों को नीट (हृश्वश्वञ्ज) एवं जेईई (छ्वश्वश्व) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु नि:शुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने का अनुमोदन किया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन एवं डॉ. रामप्रताप सिंह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने कहा कि राज्य सरकार निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हित में नई योजनाएँ प्रारंभ करने तथा वर्तमान योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए सरकार सतत प्रयासरत है, ताकि प्रत्येक पात्र निर्माण श्रमिक तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुँच सके।

अधिक मूल्य पर खाद बेचने वाली एजेंसी का विक्रय प्राधिकार पत्र निलम्बित

रायपुर. अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) एवं कांकेर जिले में कृषि विभाग के उप संचालक श्री जितेन्द्र कोमरा ने कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के पखांजूर में अधिक कीमत पर उर्वरक विक्रय किए जाने की शिकायत के विरूद्ध जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित एजेंसी का उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। भानुप्रतापपुर के अनुविभागीय कृषि अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जांच दल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) एवं उप संचालक कृषि ने बताया कि पखांजूर के कृषक श्री रवीन

मजूमदार निवासी पीव्ही 14 एवं सुदाम गाईन पीव्ही 12 को मेसर्स देवनाथ एजेंसी के प्रोप्राइटर श्री शतदल देवनाथ नया बाजार पखांजूर द्वारा कृषि सामग्री (खाद) को उचित मूल्य से अधिक कीमत पर विक्रय किए जाने के संबंध में लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में अनुविभागीय कृषि अधिकारी भानुप्रतापपुर की अध्यक्षता में जांच दल गठित की गई तथा संबंधित कृषकों के लिखित बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच दल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

जिसके लिए गौतम गंभीर ने की थी लड़ाई, कहां गायब हो गया वो खूंखार गेंदबाज

नई दिल्ली। गौतम गंभीर जब टीम इंडिया के कोच बने थे तो ये बात तय मानी जा रही थी कि वह अपने कुछ पसंदीदा क्रिकेटरों को टीम में लेकर आएंगे। ऐसा हुआ भी है। गंभीर को जिस खिलाड़ी में प्रतिभा लगी वो उसे टीम में लेकर आए, लेकिन गंभीर के टीम इंडिया की कमान संभालने के बाद जिस गेंदबाज की वापसी तय लग रही थी आज वह नदारद है।

इस गेंदबाज के लिए गंभीर ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के पदअधिकारियों से लड़ाई भी की थी। बाद में वह इसे दिल्ली टीम में लेकर आए और इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू भी किया। हालांकि, फिर टीम से बाहर हो गया और वापसी नहीं कर सका। गंभीर जब कोच बने तो लगा कि वह इस खिलाड़ी को टीम में लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं सका। इस गेंदबाज का नाम है नवदीप सैनी।

नेट्स पर दिखाया था दम

भारत के लिए दो टेस्ट, आठ वनडे और 11 टी20 खेलने वाले सैनी की कहानी दिलचस्प है। क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2013 में दिल्ली के रोशनआरा क्लब में सफेद कपड़े पहने हुए पहुंच गए। दिल्ली की रणजी टीम वहां अभ्यास कर रही थी और उसे नेट गेंदबाज की जरूरत थी। इस टीम में गौतम गंभीर भी थे। नवदीप ने गेंद उठाई और गेंदबाजी करने लगे। इस दौरान उन्होंने गंभीर को कई बार बीट किया। बस यहीं से नवदीप गंभीर की नजरों में आ गए। गंभीर ने करनाल प्रीमियर लीग का आयोजन कराने वाले सुमीत नरवाल से सैनी को लेकर बात की जिन्होंने दाएं हाथ

के इस गेंदबाज की प्रतिभा के बारे में बताया। तब सैनी मुख्यतः टेनिस गेंद से गेंदबाजी करते थे। नेट सेशन के बाद गंभीर ने नवदीप को स्पाइक्स शूज दिए और रोज दिल्ली टीम के नेट में आने को कहा।

सेलेक्टर्स बने राह में रोड़ा

यहां से नवदीप ने दिल्ली क्रिकेट में कदम रख दिए। गंभीर ने नवदीप को टीम में लाने के लिए काफी कोशिश की। उन्होंने डीडीसीए सेलेक्टर्स से भी उनके लिए लड़ाई लड़ी। इसमें उस समय के डीडीसीए उपाध्यक्ष चेतन चौहान भी शामिल थे। नवदीप का विरोध ये कहते हुए किया जा रहा था कि वह बाहरी हैं। गंभीर अपनी जिद पर अड़े रहे और नवदीप को 2013 सेशन की रणजी ट्रॉफी टीम में जगह मिली। यहां से उनका सफर आसान हो गया और तीन अगस्त 2019 को नवदीप ने लॉडेरहिल में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 के रूप में भारत के लिए अपना पहला मैच खेला।

कहां हैं नवदीप सैनी?

नवदीप ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वनडे के रूप में 23 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेला। यहां से फिर वह टीम में वापस नहीं आए। पिछले आईपीएल में वह चोटिल हर्षित राणा की जगह कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल किए गए। इस समय नवदीप दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) में खेल रहे हैं। इस लीग में वह आउटर दिल्ली वॉरियर्स से खेल रहे हैं। इस टीम का सामना गुरुवार को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स से था। नवदीप की टीम बारिश के कारण 10 ओवर प्रति पारी हुए मैच में 39 रनों से जीत हासिल की। इस मैच में सैनी ने दो ओवरों में नौ रन देकर तीन विकेट लिए। खास बात ये रही कि नवदीप शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे।

श्रीलंका पर टूटी आफत, भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले चोटिल हुआ दिग्गज बल्लेबाज; टीम परेशान

नई दिल्ली। भारतीय टीम इस समय श्रीलंका के दौर पर है जहां उसे दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। ये सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से दोनों के लिए काफी अहम है।

लेकिन इस सीरीज की शुरूआत से पहले ही मेजबान टीम पर संकट आ गया है। उसका एक स्टार खिलाड़ी चोटिल हो गया है जिससे टीम की टेंशन बढ़ गई है।

श्रीलंका की सीमित ओवरों की टीम के कप्तान कुसल मेंडिस चोटिल हो गए हैं। उनको लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) 2026 में मांसपेशियों में खिंचाव का सामना करना पड़ा है। इस लीग में वह कोलंबो कैप्स की कप्तानी कर रहे थे।

चोट पर कर रहे हैं काम

कुसल मेंडिस की चोट को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान

जारी किया है और बताया कि वह इस समय नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अपनी चोट पर काम करेंगे। बयान में उनकी चोट को लेकर किसी और तरह की जानकारी नहीं दी गई कि वह कब तक ठीक होंगे औ कितना समय लेंगे।

बयान में लिखा है, मेंडिस को 19 जुलाई को एसएससी में कोलंबो कैप्स के कैंडी रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मैच में रन लेने के दौरन मांसपेशियों में खिंचाव हो गया था। इसी के चलते वह नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाएंगे जहां और रिहैब होगा।

अगर मेंडिस की चोट ठीक नहीं होती है तो ये श्रीलंकाई टीम के लिए मुश्किल की बात है। सीरीज शुरू होने में मुश्किल से दो सप्ताह का समय बचा है। ऐसे में मेंडिस की चोट का ठीक होना मुश्किल दिख रहा है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी उनके ठीक होने की कोई टाइमलाइन नहीं बताई है। 15 अगस्त से गॉल में शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में मेंडिस टीम के अहम खिलाड़ी हैं। उनके न रहने से टीम की बल्लेबाजी पर असर पड़ेगा।

भारत दौरे से पहले साउथ अफ्रीका ने अचानक बदल दिया शेड्यूल

जोहानिसबर्ग। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने इस साल के अंत में भारतीय महिला टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे के कार्यक्रम में गुरुवार को संशोधन किया, ताकि एक टेस्ट और तीन वनडे मैच के साथ तीन टी-20 मैच को भी इसमें शामिल किया जा सके। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, एकमात्र टेस्ट मैच नौ से 12 दिसंबर तक खेला जाएगा। इसके बाद 16 से 22 दिसंबर के बीच तीन मैच की वनडे सीरीज आयोजित होगी। भारतीय महिला टीम दक्षिण अफ्रीका में एक अतिरिक्त सप्ताह तक रुकेगी और 26 से 30 दिसंबर के बीच तीन मैच की टी-20 सीरीज खेलेगी। टी-20 मुकाबले बेनोनी और पोशेफस्ट्रूम में खेले जाएंगे।

फोलेट्सी मोसेकी ताजा शेड्यूल से हुए खुश

सीएसए का मानना है कि यह सीरीज दोनों टीमों के लिए फरवरी में श्रीलंका में आयोजित होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी का बेहतरीन मौका होगी। सीएसए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) फोलेट्सी मोसेकी ने कहा कि हमें भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे के संशोधित कार्यक्रम की पुष्टि करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से लिया गया ऐसा फैसला

चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिहाज से अहम सीरीज

त्योहारों के दौरान टी-20 सीरीज को शामिल करने से हमारी महिला टीम को अगले वर्ष की शुरूआत में श्रीलंका में होने वाली पहली आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी की सर्वश्रेष्ठ तैयारी का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम में से एक है। तीनों प्रारूपों में उनके विरुद्ध खेलने का मौका हमारे लिए बेहद अहम होगा क्योंकि हम एक और बड़े आईसीसी टूनार्मेंट की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय महिला टीम ने इस साल मार्च-अप्रैल में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था जहां उसे पांच मैच की टी-20 सीरीज में 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दोनों टीमें इंग्लैंड में आयोजित महिला टी-20 विश्व कप में आमने-सामने हुईं जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराकर उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया।

इंग्लैंड के 25 वर्षीय गेंदबाज ने अचानक क्रिकेट को कहा अलविदा, सिर्फ इतने इंटरनेशनल मैच खेलकर लिया रिटायरमेंट

इंग्लैंड। 25 साल के युवा तेज गेंदबाज जॉन टर्नर ने अचानक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेकर सभी को हैरान कर दिया है. उन्हें साल 2024 में इंग्लैंड के लिए सिर्फ 4 इंटरनेशनल मैचों में खेलने का मौका मिला था, लेकिन अब उन्होंने अचानक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. पीठ में लगी गंभीर चोट के कारण जॉन टर्नर पिछले साल जून से मैदान से दूर थे. उन्होंने लगातार चोटिल होने की वजह से क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया है. बता दें कि जॉन टर्नर का जन्म जोहान्सबर्ग में हुआ था, लेकिन वो इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट खेलते थे.

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जॉन टर्नर ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू साल 2024 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान किया था. उन्होंने सीमित ओवरों के दोनों फॉर्मेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ ही अपना पहला और आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था. इसी दोनों सीरीज में उन्होंने इंग्लैंड के लिए 2 वनडे और 2 टी20 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 3 विकेट लिए थे.

जॉन टर्नर का घरेलू क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन रहा था, लेकिन लगातार चोटों से परेशान रहने के कारण वे हैम्पशायर की काउंटी चैंपियनशिप टीम में भी अपनी पक्की जगह नहीं बना पाए. वह हैम्पशायर के लिए सिर्फ 7 फर्स्ट-क्लास मैच ही खेल सके. इसके बाद, साल 2025 की शुरूआत में वह लोन पर लैंकाशायर टीम का हिस्सा बने. इस दौरान उन्होंने 3 मैच खेले, लेकिन फिर चोट की वजह से उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा. बता दें कि जॉन टर्नर का हैम्पशायर टीम के साथ उनका करार अभी दो साल और बचा हुआ था. क्या इसमें सभी जानकारी सही है

जॉन टर्नर ने अपने संन्यास पर कहा कि प्रोफेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना हमेशा से मेरा सपना रहा था. इंग्लैंड और हैम्पशायर के लिए खेलना मेरे बचपन के सपने का सच होने जैसा रहा है. टर्नर ने कहा कि मैंने क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया है और आप समझ सकते हैं कि यह मेरे लिए सबसे कठिन फैसलों में से एक रहा है. पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से मैं एक साल से ज्यादा समय से मैदान से दूर हूँ. मेरे इंजरी इतिहास ने मुझे क्रिकेट में और क्रिकेट के बाहर अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया. आखिरकार, मुझे लगा कि जिंदगी में नई चुनौतियों को चुनने का यह बिल्कुल सही समय है.

अगरकर के नाम है दर्ज हैं किंग पेयर जैसा दुर्लभ रिकार्ड

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर आजकल अपने चयन संबंधी फैसलों को लेकर सुर्खियों में हैं। अगरकर अपने समय के एक अच्छे ऑलराउंडर माने जाते रहे है हालांकि उनके नाम एक ऐसा अनचाह रिकार्ड किंग पेयर भी दर्ज है। किंग पेयर रिकार्ड बेहद दुर्लभ माना जाता है और कुछ ही खिलाड़ियों से जुड़ा है किंग पेयर क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा तकनीकी शब्द है जो टेस्ट मैच में एक बल्लेबाज के लिए सबसे शर्मनाक पलों में से एक को दिखात है। किंग पेयर उस बल्लेबाज को दिया जाता है जो किसी एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अपनी पहली ही गेंद पर बिना कोई रन बनाए आउट (गोल्डन डक) हो जाये। ये इसलिए बेहद दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि एक ही मैच में दो बार पहली गेंद पर शून्य पर कुछ ही खिलाड़ी आउट हुए हैं।

कारोबार

सेंसेक्स 350 अंकों की गिरावट के साथ खुला

नई दिल्ली। शुक्रवार को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स गिरावट के साथ खुले, जिसमें सेंसेक्स लगभग 350 अंक नीचे गिरा और निफ्टी 24,600 के नीचे ट्रेड कर रहा था। सुबह सेंसेक्स 0.40 फीसदी गिरकर 78,641.21 पर, जबकि निफ्टी 0.18 प्रतिशत गिरकर 24,592.40 पर ट्रेड कर रहा है।

बैंकिंग शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला और बैंक निफ्टी 0.36 प्रतिशत नीचे पहुंच गया। हालांकि, ब्रॉडर मार्केट ने बेंचमार्क की कमजोरी के उलट प्रदर्शन किया। निफ्टी मिडकैप 100 में 0.20 प्रतिशत की बढ़त हुई और स्मॉलकैप 100 में 0.06 प्रतिशत की मामूली बढ़त देखी गई। साल की शुरूआत से अब तक निफ्टी 50 में 5.88 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि सेंसेक्स में 7.72 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

नेस्ले इंडिया शेयर में तेजी

आज के कारोबार में नेस्ले इंडिया के शेयर अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच। ठरए पर नेस्ले इंडिया के शेयर 1,547.20 रुपये के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। अभी यह स्टॉक 1,541.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जो आज के कारोबार में 0.42% की बढ़त है।

अरबों रुपये की पाकिस्तानी खारक जब्त, आगे बड़ी तेजी के संकेत, शकर में थोड़ी नरमी

इंदौर : डायरेक्टोरेट आफ रेवेन्यू इंटेजीजेंस (डीआरआई) ने कांडला बंदरगाह पर पाकिस्तानी सूखी खजूर (खारक) की बड़ी खेप जब्त की है। 364 मिलियन टन खारक से भरे 13 कंटेनर जब्त किए गए हैं। खारक पाकिस्तान में उपजाई और प्रोसेस की हुई है। हालांकि भारत लाने के लिए इस खारक की पैदावार यूएई की बताई गई थी।

दरअसल सरकार ने पाकिस्तान से आयात प्रतिबंधित किया है। ऐसे में आयातक इसके मूल को बदलकर रूट डायवर्ट कर इसे भारत बुलवाते रहे हैं। ताजा कार्रवाई का असर आने वाले त्योहारी और सर्दियों के सीजन में पड़ेगा। दरअसल यह मात्रा काफी बड़ी है। क्विंटल के हिसाब से देखे तो यह मात्रा तीन अरब क्विंटल से ज्यादा है। इससे इंदौर समेत देश की प्रमुख खारक की थोक मंडियों में आगे माल की किल्लत हो सकती है।

खारक की अंडर बिलिंग कर माल आयात होता है

खारक की अंडर बिलिंग कर माल आयात होता है ऐसे में डीआरआइ इसकी कीमत सिर्फ 3 करोड़ रुपये बता रही है। हालांकि इस खारक का बाजार मूल्य अरबों रुपये हैं। इंदौर सियागंज में खारक के भाव इस समय 135 से 315 रुपये किलो बोले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अच्छी तेजी की उम्मीद की जा रही है।हालांकि व्यापारी कह रहे हैं कि माल जल्द छूट जाएगा लेकिन डीआरआइ के रुख से इसकी उम्मीद कम ही है। श्रावण मास में साबूदाना की बढ़ती मांग से अब भाव में जोरदार तेजी देखी जा रही है। साबूदाना के भाव बुधवार को भी बढ़ाकर बोले गए। थोक बाजार में दो महीने में शकर के कीमतों में करीब 700-800 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आ चुकी है। मई के अंत में शकर के दाम 4220-4300 रुपये प्रति क्विंटल थे जो वर्मतान में बढ़कर 5060 रुपये प्रति क्विंटल के चल रहे है। पिछले दिनों शकर ऊपर में शकर 5150 रुपये तक बिकी थी। यानि खेरची बाजार में शकर 7-8 रुपये प्रति किलो तक महंगी हो चुकी है।

शकर के बढ़ते दामों का सिलसिला सरकार द्वारा जून के कम शकर कोटे से शुरू हुआ जो जुलाई के बाद अगस्त का भी शकर कोटा खपत के लिहाज से कम जारी तेजी के सिलसिला को जारी रखा। पिछले दो महीने में शकर मिलों और स्टाकिस्टों-सटोरियों ने शकर में खूब मुनाफा कमाया।अब सरकार एथेनाल में गन्ने के उपयोग पर अंकुश लगाकर शकर के दाम करने की कोशिश में है। बुधवार को शकर के भाव में थोड़ी नरमी देखी गई। व्यापारी कह रहे हैं कि सरकार द्वारा डीलर्स के लिए स्टॉक धारिता सीमा लागू करने का निर्णय लिए जाने के बाद कुछ समय के लिए शकर के दाम में थोड़ी नरमी आ सकती है। मगर आगे पुनः इसमें तेजी का माहौल बन सकता है। अक्टूबर तक पर्व-त्योहारों का सिलसिला जारी रहेगा और नवंबर से शादी-विवाह (लग्नसरा) का सीजन शुरू होगा।

नारियल में लोकल के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की डिमांड जोरदार बनी हुई है जबकि उत्पादक केंद्रों से माल कम आने के कारण कीमतों में मंदी के आसार नहीं है। गुरुवार को नारियल की आवक एक गाड़ी की रही। खोपरा गोला और बूरे में मांग अच्छी रहने से भाव मजबूती पर टिके हुए है। तरबूज मगज की आवक बढ़ने और लेवाल सुस्त होने से भाव में मंदी रही।

सात महीने में सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट से सराफा बाजार की चाल बिगड़ी

रतलाम। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही उठा-पठक का असर अब सराफा बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। सोना-चांदी के भाव लंबे समय से निचले स्तर पर बने रहने से निवेशकों का धैर्य जवाब देने लगा है। बाजार में खरीदी-बिक्री की रफ्तार कमजोर पड़ गई है।

कारोबारियों के अनुसार वर्तमान में सोना-चांदी एमसीएक्स (मशीन) की तुलना में हाजर में कम कीमत पर उपलब्ध है, जबकि आरटीजीएस (बिल) में भाव मशीन के आसपास चल रहे हैं। भावों में बने इस अंतर से भी बाजार की सामान्य चाल प्रभावित हो रही है।

जनवरी 2026 में चांदी चार लाख रुपये प्रतिकिलो के पार पहुंच गई थी। अब यह हाजर में करीब 2.25 लाख रुपये प्रतिकिलो के स्तर पर आ गई है। इसी तरह जनवरी में 1.82 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक का स्तर छूने वाला सोना वर्तमान में करीब 1.43 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। इस तरह करीब सात माह के दौरान चांदी में 1.75 लाख रुपये प्रतिकिलो तक की बड़ी गिरावट दर्ज हो चुकी है, जबकि सोना करीब 40 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक टूट चुका है। लगातार गिरावट और अंतरराष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितता

ने सराफा कारोबारियों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। सामान्य परिस्थितियों में भावों में उतार-चढ़ाव के दौरान बाजार में खरीदी या बिकवाली के जरिए गतिविधियां बनी रहती हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में दोनों पक्षों की रफ्तार कमजोर है। न तो ग्राहक अपेक्षित रूप से खरीदी कर रहे हैं और न ही बाजार में पर्याप्त बिकवाली देखने को मिल रही है।

एक नजर सोना-चांदी के भाव पर

तारीख	चांदी	सोना			
05 अगस्त	228100	149000	30 जुलाई	222100	146200
04 अगस्त	222600	146300	29 जुलाई	224100	146200
03 अगस्त	222600	146400	28 जुलाई	223500	146200
01 अगस्त	225100	146600	27 जुलाई	229100	148000
31 जुलाई	224100	146600	25 जुलाई	227100	147000

निवेशकों के सामने चिंता

भावों में आई बड़ी गिरावट ने निवेशकों की रणनीति भी प्रभावित की है। ऊंचे स्तर पर खरीदारी करने वाले निवेशकों के सामने वर्तमान भाव चिंता का कारण बने हुए हैं। दूसरी ओर नए निवेशक भी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और बाजार की दिशा स्पष्ट नहीं होने के कारण निर्णय लेने में सावधानी बरत रहे हैं। कारोबारियों की चिंता इस बात को लेकर बढ़ रही है कि लंबे समय तक बाजार में लेवाली और बिकवाली कमजोर रहने से सराफा कारोबार की सामान्य गति और प्रभावित हो सकती है। सराफा व्यवसायी ऋषभ संघवी और प्रतीक जैन का कहना है कि लंबे समय से बाजार की चाल सुस्त पड़ी है। थोड़े-थोड़े अंतराल में भाव ऊपर-नीचे हो रहे हैं। इससे ग्राहकी नहीं के बराबर है। गिरावट के दौर में खरीदार भाव और नीचे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भाव और नीचे आने से खरीदी का माहौल बन सकता है।

एमपी के स्थानीय चुनावों में दिखेगा ऐतिहासिक बदलाव

2027 में ईवीएम से चुने जाएंगे पंच और सरपंच, आयोग ने कसी कमर

भोपाल। मध्यप्रदेश में जून और जुलाई 2027 में होने वाले आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं।

इस बार के चुनावों में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा, जहां आयोग पंचायतों में पंच और सरपंच पदों का मतदान भी बैलेट पेपर की जगह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (एएट) के जरिए कराने की योजना बना रहा है। यदि यह नई व्यवस्था अमल में आती है, तो प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्थानीय निकाय और पंचायत के सभी पदों के चुनाव 100% ईवीएम से संपन्न होंगे। इससे मतगणना में पारदर्शिता आएगी और चुनाव परिणाम भी काफी तेजी से घोषित किए जा सकेंगे। तैयारियों को लेकर गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग में पहली उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें 44 जिलों के उप निर्वाचन अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स शामिल हुए।

दो चरणों में होगी मतदान प्रक्रिया

नगरीय निकाय चुनाव (जून 2027): प्रदेश की 413 नगरीय संस्थाओं में जून महीने में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए राज्यभर में 22 हजार पोलिंग बूथ तैयार किए जाएंगे। पंचायत चुनाव (जुलाई 2027): निकाय चुनावों के ठीक अगले महीने यानी जुलाई में लगभग 23 हजार ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे, जिनके लिए 72 हजार मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2022 के चुनावों में निकाय सदस्यों के साथ-साथ केवल जिला व जनपद पंचायत सदस्यों का चुनाव ही ईवीएम से हुआ था, जबकि पंच और सरपंच पदों के लिए परंपरागत मतपत्रों का प्रयोग किया गया था। चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए मतदान केंद्रों से लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके अलावा, अंतर-राज्यीय सहयोग के तहत मध्यप्रदेश द्वारा अन्य राज्यों (जैसे–त्रिपुरा, सिक्किम, महाराष्ट्र और राजस्थान) को भी स्थानीय चुनावों के लिए ईवीएम मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।

तकनीक के साथ जनता का विश्वास कायम रखना जरूरी: राज्य निर्वाचन आयुक्त

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चुनाव से जुड़ी हर तकनीकी समस्या का समय रहते समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनाव जनता से सीधे जुड़े और बेहद संवेदनशील होते हैं, इसलिए नए तकनीकी बदलावों को अपनाते हुए यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि निर्वाचन प्रक्रिया पर मतदाताओं का भरोसा अटूट बना रहे।

महत्वपूर्ण ख़बर

प्रदेश में 1 से 15 अगस्त तक आयोजित हो रहा विशेष स्वनिधि पखवाड़ा

- भोपाल। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिकाधिक पात्र पथ विक्रेताओं को योजना से लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक विशेष "स्वनिधि पखवाड़ा" आयोजित किया जा रहा है। अभियान के दौरान सभी जिलों, नगरीय निकायों एवं संबंधित सेन्सस टाउन में व्यापक जनजागरूकता, नवीन ऋण आवेदन, UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड आवेदन, लंबित एवं रिटर्न ऋण प्रकरणों के निराकरण सहित विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही है, पखवाड़े अंतर्गत प्रारंभिक 5 दिनों में कुल 8,377 ऋण प्रकरण राशि रु. 25.00 करोड़ के वितरित किये जा चुके है, अभियान अंतर्गत पिछले 5 दिनों में 1,575 नवीन पथ-विक्रेताओ को योजना से जोड़ा गया है। 8,86 नवीन क्रेडिट कार्ड के आवेदन बैंको में प्रेषित कर पथ विक्रेताओं को जारी किये गए है।

मध्यप्रदेश हॉकी टीम ने रचा जीत का नया अध्याय

- भोपाल। मध्यप्रदेश की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप-2026 के फाइनल में प्रवेश कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। कोयंबटूर में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में मध्यप्रदेश ने मजबूत प्रतिद्वंद्वी हॉकी झारखंड को 2-0 से पराजित कर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह सुनिश्चित की। टीम का यह प्रदर्शन खिलाड़ियों के अनुशासन, रणनीति और जुझारू खेल का शानदार उदाहरण रहा।

'प्राइवेट सेंटरों में मुफ्त होगी गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी'

मातृ-शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए एमपी सरकार का बड़ा कदम

भोपाल। अब गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए सरकारी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन खराब है या डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो उनकी सोनोग्राफी निजी सेंटरों में बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी। इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत इसके नए निर्देश जारी किए हैं। इस व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और कैशलेस कर दिया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।

इस तरह होगी प्रोसेस

सरकारी अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ, पीजीएमओ या मेडिकल ऑफिसर ओपीडी में जांच के बाद सोनोग्राफी की सलाह देंगे। इसके

बाद महिला के मोबाइल पर एसएमएस के जरिए ई-वाउचर भेजा जाएगा। इस ई-वाउचर से महिला 7 दिनों के भीतर किसी भी अधिकृत निजी सोनोग्राफी सेंटर पर जाकर मुफ्त जांच करवा सकेगी।

आपातकाल में जरूरत होने पर एक गर्भवती की अधिकतम दो बार तक सोनोग्राफी कराई जा सकेगी। यह सुविधा खासकर उन जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए है जहां सरकारी सोनोलाजिस्ट नहीं हैं या वे लंबे अवकाश पर हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत चिन्हित सभी स्वास्थ्य संस्थाओं से भी रेफर किया जा सकेगा।

पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

निजी सेंटरों में होने वाली हर सोनोग्राफी की रिपोर्ट और मरीज की जानकारी ओडीके ऐप के जरिए सीधे ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। इससे रिपोर्ट में हेराफेरी नहीं हो सकेगी। भुगतान के लिए सुमन यूएसजी पोर्टल बनाया गया है। निजी सेंटर संचालक को अपना बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। जांच के बाद सेंटर ई-वाउचर बनाएगा, जिसे अस्पताल अप्रूव करेगा। अप्रूवल के बाद 500 रुपये प्रति केस का भुगतान सीधे सेंटर के खाते में स्पर्श पोर्टल के जरिए कर दिया जाएगा।

मां और बच्चे दोनों को होगा फायदा

गर्भावस्था के दौरान समय पर सोनोग्राफी से मां और बच्चे को होने वाले खतरे और बीमारियों की पहचान शुरूआती दौर में ही हो जाएगी। इससे समय पर इलाज मिलेगा और मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। यह योजना पूरे प्रदेश में लागू है। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सीएमचओ कार्यालय भोपाल ने निजी सोनोलाजिस्टों को प्रशिक्षण दिया। उन्हें ई-वाउचर बनाना, रिकार्ड रखना और भुगतान प्रक्रिया की जानकारी दी गई। सुमन यूएसजी पोर्टल पर गर्भवती की सोनोग्राफी की स्पेशल फाइंडिंग्स देखकर गर्भावस्था के जोखिमों की जानकारी लेना अब आसान हो गया है।

इस डिजिटल सिस्टम से महिलाएं समय पर मुफ्त जांच करवा सकेंगी और हमें मरीज का पूरा रिकार्ड तुरंत मिल जाएगा। निजी सेंटरों के सहयोग से हम हर महिला तक यह सुविधा पहुंचाना चाहते हैं।

डॉ. मनीष शर्मा, सीएमएचओ, भोपाल।

इंदौर-प्रयागराज स्पेशल ट्रेन को झींझक स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव

इंदौर। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए इंदौर-प्रयागराज (सूबेदारगंज) स्पेशल ट्रेन रतलाम मंडल से होकर गुजरेगी। इस ट्रेन झींझक स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है। अतिरिक्त ठहराव देने का फायदा इस रूट पर आवागमन करने वाले यात्रियों को मिलेगा।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार आठ अगस्त से 29 सितंबर तक इंदौर से चलने वाली ट्रेन इंदौर-सूबेदारगंज स्पेशल झींझक स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन झींझक स्टेशन पर दोपहर 03:55 बजे पहुंचेगी और दोपहर 03:57 बजे प्रस्थान करेगी। इस ठहराव से इस लाइन पर यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ होगा।

ट्रेन झींझक स्टेशन पर सुबह 09:03 बजे पहुंचेगी

इसी प्रकार सात अगस्त से 28 सितंबर तक सूबेदारगंज से चलने वाली ट्रेन सूबेदारगंज-इंदौर स्पेशल झींझक स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन झींझक स्टेशन पर सुबह 09:03 बजे पहुंचेगी और सुबह 09:05 बजे प्रस्थान करेगी। रतलाम : यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने रेल मंडल से गुजरने वाली अहमदाबाद-पटना स्पेशल ट्रेन का एक फेरा बढ़ाया है।

अहमदाबाद-पटना स्पेशल ट्रेन का एक फेरा बढ़ाया

मंडल जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार ट्रेन 09447 अहमदाबाद-पटना स्पेशल 12 अगस्त 2026 को अहमदाबाद से चलेगी तथा 09448 पटना-अहमदाबाद स्पेशल 14 अगस्त को पटना से रवाना होगी। ठहराव, समय और ट्रेन संरचना की विस्तृत जानकारी पर तथा रेलवन एप से प्राप्त की जा सकती है।

11 अगस्त की ट्रेन भुसावल-अकोला-पूर्णा होकर संचालित होगी

रतलाम : मध्य रेलवे के भुसावल मंडल स्थित भादली स्टेशन पर ब्लाक के कारण रेल मंडल से होकर गुजरने वाली हिसार-हैदराबाद एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। मंडल जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार 11 अगस्त को हिसार से चलने वाली 17019 हिसार-हैदराबाद एक्सप्रेस भुसावल-अकोला-पूर्णा होकर चलेगी।

इंदौर में नाबालिग प्रेमिका के माता-पिता की हत्या करने वाले को दोहरा आजीवन कारावास

इंदौर। नाबालिग प्रेमिका के साथ मिलकर उसके माता-पिता की हत्या करने वाले हत्यारे प्रेमी को सेशन कोर्ट ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। यह प्रकरण चिह्नित प्रकरणों की सूची में शामिल था और इसकी प्रतिमाह समीक्षा भी की जा रही थी। हत्यारे का नाम डीजे उर्फ धनंजय उर्फ शुभांषु यादव निवासी गांधीनगर है। कोर्ट ने हत्यारे पर 33 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आरती भदौरिया ने पैरवी की।

वारदात 16 दिसंबर 2020 की रात की है। रूकमणी नगर निवासी फरियादी 18 वर्षीय ऋषभ शर्मा ने एरोड्रम पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी माता नीलम शर्मा

और पिता ज्योतिप्रसाद शर्मा की हत्या कर दी है। उसने पुलिस को बताया था कि वह माता-पिता और बहन के साथ रहता है। उसके घर के पास ही दूसरे मकान में उसके दादा-दादी भी रहते हैं। 16 दिसंबर 2020 की रात उसके माता-पिता और छोटी बहन उसके घर में सो रहे थे जबकि वह खुद दादा-दादी के घर सो रहा था। सुबह करीब आठ बजे उसने देखा कि उसके माता-पिता के घर के बाहर ताला लगा है। खिड़की से झांककर देखा तो पिता ज्योतिप्रसाद शर्मा और मम्मी नीलम शर्मा खून से लथपथ पड़े थे।

ताला तोड़कर वह भीतर गया तो देखा कि किसी ने दोनों के सिर और शरीर पर धारदार हथियार से चोट की थी। घर पर छोटी बहन भी नहीं थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामले की जांच के दौरान पुलिस को मृतक के घर से उसकी नाबालिग बेटी की कापी में एक पेज लिखा हुआ मिला। इसमें लिखा था की मैने ही अपने माता-पिता को मारा है। मुझे ढूंढने का प्रयास नहीं किया जाए।

विशेष लोक अभियोजक भदौरिया ने बताया कि पुलिस ने मृतक के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो बेटी के अलावा एक अन्य संदिग्ध व्यक्ति घर के अंदर आते-जाते नजर आया। जांच में मृतक के स्वजन ने बताया कि यह नाबालिग बेटी का दोस्त धनंजय है। प्रकरण की जांच करते हुए पुलिस नाबालिग बेटी और धनंजय तक पहुंची। दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपितों से अपराध में उपयोग की गए हथियार भी जब्त किए। नाबालिग के विरुद्ध बाल न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। विशेष लोक अभियोजक भदौरिया ने बताया कि प्रकरण में घटना स्थल के दरवाजे पर चिंगम के मिलने पर हत्यारे धनंजय के स्वाव का परीक्षण भी कराया गया था। उपनिदेशक अभियोजन राजेंद्रसिंह भदौरिया ने बताया कि सेशन जज हेमंतकुमार रघुवंशी ने प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए हत्यारे धनंजय को दोहरे आजीवन कारावास और 33 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

मध्यप्रदेश द्वारा हरित ऊर्जा के लिये किये जा रहे कार्य की विश्वभर में चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा सम्मेलन के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में कहा कि मध्यप्रदेश हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे तेज गति से कार्य कर रहा है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उत्पादन के प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। इस तरह का ऊर्जा उत्पादन 24 घंटे होगा। इस पर कार्य जारी है और मध्यप्रदेश द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे कार्य की विश्वभर में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश हरित ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया एक्स में एक संदेश में कहा कि मध्यप्रदेश भारतीय रेलवे सहित 8 राज्यों में ऊर्जा की आपूर्ति का कार्य कर रहा है।

इंदौर में 1.68 लाख रुपये में बिका '0001', 75 हजार में '0007'

त्योहारों के लिए भी धड़ल्ले से हो रही बुकिंग

इंदौर

इंदौर आरटीओ (एमपी-09) में वाहनों के खास और फैंसी नंबरों की ई-नीलामी का अनोखा रिकॉर्ड बना है। 2022 में ऑनलाइन ऑक्शन शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि गुरुवार शाम 5 बजे बंद होने वाली बोली लगातार चलते रहने के कारण 5.58 बजे (58 मिनट अतिरिक्त) तक जारी रही। श्रावण मास और आगामी त्योहारों (रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेशोत्सव) को देखते हुए 'टढ09 इश' सीरीज में 108 फैंसी नंबरों पर बोली लगी। आम दिनों में सामान्यतः 80 से 90 नंबरों के लिए ही आवेदन आते हैं।

10 हजार से 14 लाख तक बिक चुका है '0001' नंबर

कौन-सा नंबर कितने में बिका

0001 : 1.68 लाख (बेस प्राइस : 1 लाख)
0007 : 75,000
5555 : 66,000
0002, 0005, 0009 : 50,000 प्रत्येक (बेस प्राइस : 50 हजार)
1111 : 35,500
0900 : 29,500
0021 : 29,000
9999 : 28,000
7777 : 25,000

वीआईपी नंबरों का बेस प्राइस गणित (कैटेगरी अनुसार)

0001 : 1 लाख
0002 से 0009 : 50,000
0010 से 0099 : 25,000
0100 से 0999 : 15,000

(नोटः आरटीओ की हर नई सीरीज में 419 से 429 वीआईपी/खास नंबरों को नीलामी की श्रेणी में रखा जाता है।)

इंदौर आरटीओ में '0001' नंबर का क्रेज हमेशा से रहा है।

पूर्व में यह नंबर 14 लाख तक की उच्चतम बोली में बिका है, जबकि 2.5 लाख से 9 लाख तक में भी कई बार बिका। एक बार फोर-व्हीलर श्रेणी में कोई आवेदन न आने पर टू-व्हीलर के आवेदक को यह नंबर महज 10 हजार (बेस प्राइस) में मिल गया था। मध्यप्रदेश परिवहन विभाग गाड़ी मालिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर ला रहा है। अब वाहन बदलते समय अपना पसंदीदा, लकी या स्टेटस सिंबल वाला पुराना नंबर खोने की चिंता खत्म हो जाएगी। विभाग एक ऐसी सरल व्यवस्था बना रहा है, जिससे आप अपने पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी नई गाड़ी पर आसानी से ट्रांसफर करवा सकेंगे। बता दें कि पुराने वाहन का नंबर नई गाड़ी पर लेने की सुविधा स्क्रैप पॉलिसी के तहत पहले से मौजूद है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अत्यंत जटिल और समय लेने वाली है। इस कारण बहुत कम लोग ही इसका लाभ उठा पाते हैं। अब परिवहन विभाग इस पूरी प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने जा रहा है।

किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?

इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को मिलेगा जो वीआईपी (श्रृंखला), लकी या स्टेटस नंबर रखने के शौकीन हैं और अपनी हर नई गाड़ी पर वही खास पहचान बनाए रखना चाहते हैं।

खरगोन में 10 अवैध पिस्टल के साथ हरियाणा और यूपी के तस्कर गिरफ्तार

खरगोन। पिस्टल खरीदकर लौट रहे हरियाणा व उत्तर प्रदेश के दो तस्करों को पकड़ा गया है। आरोपित पुलिस से बचने के लिए बिना नंबर की कार की सीट के नीचे हथियार छिपाकर ले जा रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 अवैध देशी पिस्टल व वाहन जब्त किया है।

जिले की बिस्टान, भीकनगांव व गोगावां थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिगनूर से बिना नंबर की कार में दो संदिग्ध युवक हथियार लेकर खरगोन की ओर आ रहे हैं।

सूचना पर भीकनगांव एसडीओपी केतन अडलक के नेतृत्व में बिस्टान थाना प्रभारी गुलाब सिंह रावत, भीकनगांव थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौड़ व गोगावां थाना प्रभारी दीपक यादव की टीम ने ग्राम रसगांगली में यात्री प्रतीक्षालय के पास खड़ी संदिग्ध कार की घेराबंदी की। गाड़ी में बैठे रोकेश (33) पिता उदयवीर जाट निवासी पलवल (हरियाणा) व रोहित (26) पिता श्रीपाल सारस्वत निवासी मथुरा (उत्तर प्रदेश) को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई। सीट के नीचे रखी थैली से 10 अवैध देशी पिस्टल बरामद हुईं।

सिगनूर से खरीदना किया स्वीकार

पूछताछ में आरोपितों ने कबूल किया कि उन्होंने यह हथियार सिगनूर के एक स्थानीय तस्कर से खरीदे थे। बिस्टान पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अब सिगनूर के उस मुख्य सप्लायर की तलाश कर रही है।

निर्वाचन कार्यों में छोटी सी लापरवाही अविश्वास का बन जाती है कारण

भोपाल। निर्वाचन कार्यों में छोटी सी लापरवाही अविश्वास का कारण बन जाती है। अतः प्रशिक्षण कार्यशाला में अपनी सभी शंकाओं का समुचित समाधान करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दें। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज श्रीवास्तव ने यह बातें उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और मास्टर ट्रेनर्स की राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में कही।

ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव-2026 में हुआ छह देशों की सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन

भोपाल। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता-2026 के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को रवींद्र भवन, भोपाल में ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव-2026 आयोजित किया गया। ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक के दूसरे दिन आयोजित इस महोत्सव में ब्रिक्स सदस्य एवं शामिल देशों के कलाकारों ने अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से विभिन्न देशों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचय कराया और सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी सहयोग की भावना को सशक्त बनाया।

महोत्सव का आयोजन सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना पर आधारित था, जो सार्वभौमिक शांति, सद्भाव और सामूहिक कल्याण के भारत के सभ्यतागत दर्शन को अभिव्यक्त करता है। यह आयोजन भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता-2026 की थीम लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और निरंतरता के लिए निर्माण के अनुरूप विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और जन-जन के आपसी संबंधों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिभागी देशों की सांस्कृतिक परेड के साथ हुआ। इसमें बेलारूस, ब्राजील, इंडोनेशिया, रूसी संघ, संयुक्त अरब अमीरात और मेजबान भारत के सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों ने शामिल होकर वैश्विक एकता और सांस्कृतिक सौहार्द का परिचय दिया। बेलारूस के गेनाडी त्सितोविच नेशनल एकेडमिक लोक कॉयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बेलारूस के कलाकारों ने पारंपरिक बेलारूसी लोकगीतों और हास्य लोकनृत्यों की प्रस्तुति दी।

ब्राजील की ओर से एफ्रो-ब्राजीलियाई सांस्कृतिक परंपरा कैपोएरा का प्रदर्शन किया गया। इस प्रस्तुति में मार्शल आर्ट, नृत्य, संगीत और एक्रोबैटिक कलाओं का अनूठा संगम देखने को मिला इंडोनेशिया के कलाकारों ने पारंपरिक बालीनीज स्वागत नृत्य पुष्पांजलि प्रस्तुत किया। इसके साथ ही प्रंबनन मंदिर से प्रेरित प्रसिद्ध जावानीस नृत्य-नाटिका द लीजेंड ऑफ रोरो जोंगरांग का मंचन किया। रूसी संघ के नेशनल एकेडमिक लोक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्केस्ट्रा ऑफ रूस के एकल कलाकारों ने बालालाइका, बायान, ऑल्टो डोमरा और कॉन्ट्राबास बालालाइका जैसे पारंपरिक रूसी वाद्ययंत्रों पर संगीतमय प्रस्तुति दी।संयुक्त अरब अमीरात के प्रसिद्ध संगीतकार सैफ अल-अली ने समकालीन प्रभावों के साथ अमीराती और अरब संगीत परंपराओं की प्रस्तुति दी।भारत की ओर से ह्लमारू रंग - राजस्थान की विरासतह्व कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इसमें घूमर, चरी, कालबेलिया और भवाई जैसे लोकनृत्यों के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।